● वर्ष-2
● अंक-192
रायपुर, मंगलवार
04 अप्रैल 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmailÐcom

भ्रष्टाचारियों को भूपेश का संरक्षण-डॉ. रमन

पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं नान मामले की जाँच ईडी पहले से कर रही है

रायपुर। ईडी, नान घोटाले और चिटफंड मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी भ्रष्टाचारी के घर छापा पड़े तो सबसे पहली प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सामने आती है। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि इस प्रतिक्रिया में वह भ्रष्टाचार का विरोध नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों का समर्थन करते हैं और जांच पर सवाल उठाते हैं।

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की बदौलत एक परंपरा चल पड़ी है कि जिसके घर भी छापा पड़ता है वो व्यक्ति शर्म से सर झुकाने की जगह सीना चौड़ा करके चलता है। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के भीतर जो यह आत्मविश्वास बढ़ा है, यह भूपेश बघेल के समर्थन से ही हुआ है। पूर्व में पड़े आयकर विभाग के छापों से प्राप्त दस्तावेज के आधार पर वर्तमान में प्रदेश में जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं। इन छापों के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षक बनकर सामने आ जाते हैं और श्रष्ठ के अधिकारियों को धमकी देने लगते हैं, उनकी जांच और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाते हैं।

नान घोटाले पर मुख्यमंत्री की नीयत पर सवाल उठाते हुए डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जब-जब इस सरकार पर जांच का घेरा कसने लगता है तब भूपेश बघेल नान मामले के चिराग से सीएम मैडम नाम का जिन्न निकाल लेते हैं। मैं उन्हें एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि आपकी सरकार की गठित एसआईटी ने ही अपनी जांच रिपोर्ट में साफ़-साफ़ लिखा था कि सीएम मैडम चिंतामणि हैं। अब या तो भूपेश बघेल जी ने रिपोर्ट पढ़ी नहीं या फिर वो सब जानते हुए भी जनता के सामने झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। 2015 में जब दो वरिष्ठ अधिकारियों का नाम नान घोटाले में सामने आया तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन पर तत्काल कार्यवाही करते ही चार्जशीट दायर की और उन्हें निलंबित किया जिन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध हमारी सरकार ने मुकदमे दायर किए उन्हें कांग्रेस की सत्ता आते ही बड़े पदों से सम्मानित किया गया। इन अधिकारियों पर जब आयकर विभाग ने कार्यवाही की तब

उनके व्हाट्सएप चैट से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो साबित करते हैं कि किस तरह से भूपेश बघेल भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षक बनकर काम कर रहे थे।

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि एक तरफ भूपेश बघेल नान घोटाले के प्रमुख आरोपी अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के विरुद्ध सीबीआई और ईडी से जांच हेतु प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते हैं और दूसरी तरफ यही भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार आते ही न केवल उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में संरक्षण देते हैं बल्कि प्रदेश के महत्वपूर्ण पदों में भी बैठा देते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नान मामले में ईडी द्वारा जाँच की मांग करने के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि, मुख्यमंत्री भूपेश जी नान मामले की जांच ईडी पहले से कर रही है और प्रदेश से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना चाहती है ताकि निष्पक्ष जांच हो तो भूपेश बघेल उसमें अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं?

जिस तरह भूपेश बघेल ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर मेरी छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और अंत में जब न्यायालय का निर्णय आया तब इस पूरे घटनाक्रम को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। चिटफंड के मामले में, मैं आप सभी के सामने राजनांदगांव का उदाहरण रखना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिना किसी आधार और साक्ष्य के सिर्फ चिटफंड पर आक्षेप करते रहते हैं। जबकि सत्य यह है कि इस मामले में भूपेश बघेल की पुलिस और उनकी एसआईटी ने जांच की है और जांच उपरांत स्पष्ट रूप से कहा कि विवेचना में अपराध में शामिल धारा के दंडनीय कृत्य के संबंध में स्टार प्रचारकों द्वारा प्रत्यक्ष कार्य किया जाना अथवा कार्यलोभ घटित होना स्थापित नहीं हुआ।

सौम्या और समीर का मामला ईओडब्ल्यू को सौंपा

छत्तीसगढ़ के दो अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू से जांच कराने के संबंध में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की चिट्ठी पर राज्य शासन जांच के आदेश दे दिए हैं. सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि ईडी डायरेक्टर की ओर से हमारे दो अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए जो चिट्ठी मिली थी, उस पर हमने जांच शुरू कर दी है, लेकिन हमने चिटफंड घोटाले और नान घोटाले की जांच के लिए जो चिट्ठी लिखी थी, उसकी जांच कब होगी? डायरी में जो सीएम सर और सीएम मैडम का उल्लेख है, उसके यहां जांच के लिए कब जाएंगे? चिटफंड घोटाले में जो लोग शामिल थे और जिन लोगों ने रोजगार मेला आयोजित कर प्रमाण पत्र बांटे थे, उनके यहां जांच करने कब जाएंगे? इससे पहले सीएम ने कहा कि ईडी एक साल से जांच कर रही है. एक महीने में 50 छापे डाल दिए. क्या-क्या पाया, यह बताएं. देश के सबसे कड़े कानून के तहत ईडी जांच कर रही है, क्या पाया? जब कुछ नहीं पाए, तब राज्य सरकार को जांच के लिए दे दिया. क्यों दिया ? कुछ मिला होता तो राज्य सरकार को देने का सवाल नहीं उठता. फिर भी हमने जांच के आदेश हैं. भाजपा विधायकों की पीएम नरेंद्र मोदी के साथ 5 अप्रैल को होने वाली मीटिंग पर भी सीएम भूपेश ने तंज किया है. उन्होंने कहा कि साढ़े चार साल छत्तीसगढ़ की सुध नहीं ली।

इन दिनों

✍ शशांक शर्मा

विश्वविद्यालय के नए कुलपति

देश में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों के स्थापना के बाद उसके प्रमुख को कुलपति शब्द से संबोधित किया जाने लगा। विश्वविद्यालय में कुलपति का अधिकार सर्वोच्च होता है, यहां तक कि प्रशासनिक अमला भी बिना कुलपति की अनुमति के विश्वविद्यालय परिसर में नहीं जा सकता था। समय के साथ परिस्थितियां बदली है और कुलपति पद, शब्द, और शुसोभित करने वालों व्यक्तियों के स्तर में गिरावट आई है। शायद उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में गिरावट का यह एक मूल कारण है। भारतीय सेवा के अधिकारियों को अपने पद का दंभ होता है। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति को अपने प्राध्यापक होने का एक अभिमान भी होता है इसलिए दोनों अधिकारियों के बीच सामंजस्य कम ही बैठ पाता है। एक समय था यह विश्वविद्यालय के कुलपति का स्थान नौकरशाही में सचिव के पद से ऊंचा होता था। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन करके अब विश्वविद्यालय के कुलपति के स्थान को उप सचिव के बराबर कर दिया गया है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में कुलपति के नियुक्ति को लेकर पिछले चार वर्षों से विवाद चल रहा है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और राज्यपाल मोदी सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते है इसलिए नियुक्ति में आपसी सामंजस्य का अभाव देखा गया है। जिस विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार के मनमुताबिक न हो तो विश्वविद्यालय के काम-काज भी प्रभावित किए जाते है। अजीब सोच है शीर्ष लोगों के विवाद के चलते शैक्षणिक संस्था की प्रतिष्ठा धूमिल होती है और छात्रों का नुकसान होता है। राजधानी के सबसे पुराने पं. रविशंकर विश्वविद्यालय में डा. सच्चिदानंद शुक्ल नए कुलपति बनाए गए है। वे उत्तरप्रदेश के अयोध्या के है इसलिए स्थानीय कुलपति की मांग को लेकर उनकी नियुक्ति पर विवाद हुआ था। डॉ. शुक्ला ने पदभार ग्रहण कर लिया है और अपने भावी योजनाओं के बारे में भी बताया है। ऐसा होता है जब कोई नया कुलपति पद ग्रहण करते है तो बाते बड़ी-बड़ी की जाती है लेकिन विश्वविद्यालय के राजनीति और समस्याओ में ऐसे उलझतें है कि सारी योजनाएं फुर्र हो जाती है। डॉ. शुक्ला ने भी विश्वविद्यालय की छबी सुधारने और अकादमी कार्य को बेहतर करने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। लेकिन उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में एक म्यूजियम बनाने की बात कही है जहां छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को सहेजा जाएगा। वैसे तो यह कार्य खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय को करना चाहिए। दूसरी बात यह कार्य करने के लिए राजधानी में संस्कृति विभाग है और पुरखौती मुक्तांगन में म्यूजियम बनाकर ऐसा किया जा रहा है। रविशंकर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी छत्तीसगढ़ के है जो अपनी संस्कृति से परिचित है। नए कुलपति डॉ. शुक्ला का ध्यान अकादमिक उन्नति करनें में होना चाहिए। पर क्या करें प्रदेश सरकार जब छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है तो कुलपति भला कहा पीछे रहने वाले।

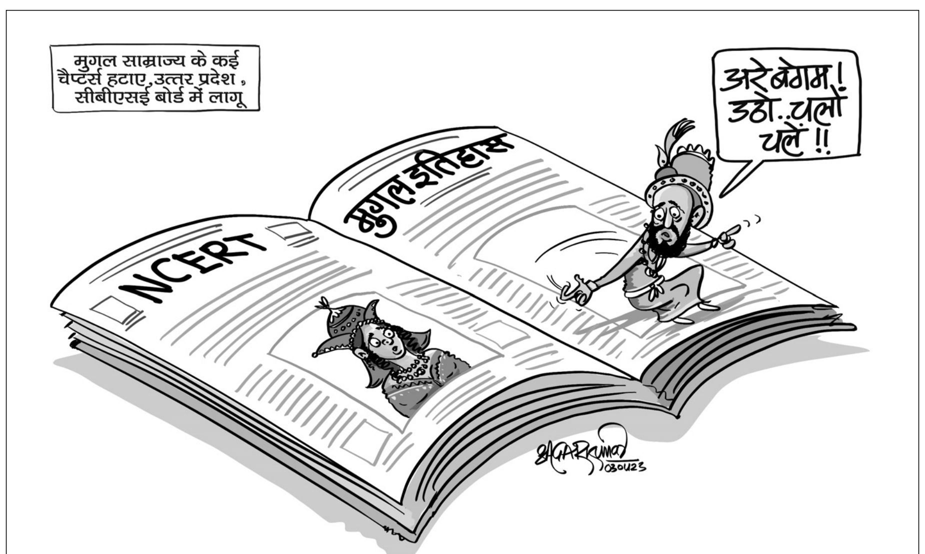

फिर दुनिया के ज्यादा संक्रमित देशों की सूची में पहुंचा भारत

■ **24 घंटे में रिकॉर्ड केस मिले, 11 मौतें**

नई दिल्ली। कोरोना से जुड़ी बुरी खबर है। भारत एक बार फिर से दुनिया उन पांच देशों में शामिल हो गया है, जहां इन दिनों सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के रिकॉर्ड केस बढ़े हैं। इस बीच, 3,641 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 20 हजार 219 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य

मंत्रालय के अनुसार, रविवार को संक्रमण की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें चार केरल, तीन महाराष्ट्र और दिल्ली, कर्नाटक और राजस्थान से एक-एक मौतें शामिल हैं। इसी के साथ कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर पांच लाख 30 हजार 892 हो गई है।

दैनिक सकारात्मकता दर 6.12 दर्ज की गई जबकि साप्ताहिक सकारात्मकता 2.45 प्रतिशत आंकी गई।

देश में अब तक चार करोड़ 47 लाख 26 हजार 246 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 0.05 प्रतिशत लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि चार करोड़ 41 लाख 75 हजार 135 लोग ठीक हो चुके हैं। 1.19 प्रतिशत लोगों की मौत हो चुकी है।

मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220.66 करोड़ कोविड टीके की खुराक दी जा चुकी है। आंकड़ों के अनुसार, भारत एक बार फिर से उन पांच देशों की सूची में शामिल हो गया है, जहां सबसे ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। रविवार को दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा 9724 लोग संक्रमित पाए गए। दूसरे नंबर पर रूस में 9,591, जापान में 6290, फ्रांस में 6027 लोग संक्रमित मिले। इसके बाद भारत में 3,641 लोग संक्रमित पाए गए।

प्रमुख समाचार

'मित्रकाल' के खिलाफ, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है- राहुल

नयी दिल्ली। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मानहानि के मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर करने के बाद सोमवार को कहा कि वह 'मित्रकाल' के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें सत्य ही उनका अस्त्र है। उन्होंने ट्वीट किया, ''ये 'मित्रकाल' के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में, सत्य मेरा अस्त्र है, और सत्य ही मेरा आसरा!'' कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उनके इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, ''सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। राहुल गांधी ने 'मोदी उपनाम' के संदर्भ में उनकी 2019 की टिप्पणी से संबंधित मानहानि के एक मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ सोमवार को सत्र अदालत में अपील दायर की। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। एक अधिकारी ने बताया कि सत्र अदालत मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को करेगी। राहुल को पिछले महीने यहां की निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और दो साल के लिए जेल की सजा सुनाई थी। दो भगोड़े कारोबारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'उपनाम' के बारे में अपनी टिप्पणी में राहुल गांधी ने कहा था कि सारे 'चोरों' के 'उपनाम' मोदी क्यों हैं।

अडानी की कंपनी के चेयरमैन बने पूर्व इजरायली राजदूत महुआ मोइत्रा ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। भारत में इज़राइल के पूर्व राजदूत रॉन मलका ने रविवार को कहा कि उन्होंने हाइफ़ा पोर्ट कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जिसका स्वामित्व अडानी पोर्ट्स एंड

स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड और गैडोट ग्रुप के एक संघ के पास है। मलका ने ट्वीट करते हुए कहा कि अडानी लिमिटेड की ओर से हाइफा पोर्ट कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आज पदभार ग्रहण करने के लिए सम्मानित और सम्मानित महसूस कर रहा हूं। अडानी और गैडोट का अनुभव बंदरगाह श्रमिकों के समर्पण के साथ संयुक्त रूप से हाइफा बंदरगाह को समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा कि अडानी हमाम में तो सारे नंगे हैं। महुआ ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत अडानी के हाइफा बंदरगाह के अध्यक्ष नियुक्त! यह आदमी छतों से चिल्लाया कि अडानी के इजराइली सौदे कितने साफ थे। बॉलीवुड हिंदुत्व प्रचार फिल्म की आलोचना करने के लिए फिल्म निर्माता नदव लैपिड की निंदा की।

पाकिस्तान का दोस्त बताए जाने पर नाराज हुए दिग्विजय सिंह

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश प्रभारी पी

मुरलीधर राव पर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी। सिंह ने इस मुद्दे पर एक समाचार रिपोर्ट की छवि के साथ ट्वीट किया जिसमें दावा किया गया था कि राव ने ऐसी टिप्पणी की थी। नई रिपोर्टों के अनुसार, शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आधिकारिक निवास में एक समारोह में कथित तौर पर राव द्वारा सिंह को पाकिस्तान का दोस्त मानने सहित यह टिप्पणी की गई थी। सिंह ने कहा कि आपने जो आरोप लगाए हैं, उनके लिए आपको अदालत में जवाब देना होगा। कार्यक्रम में मुरलीधर राव ने कहा था कि कार्यक्रम में मुरलीधर राव ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में इतने सालों पहले सत्ता में आ गए थे कि आपमें से कई लोगों का जन्म ही नहीं हुआ होगा। कुछ युवाओं को उस वक्त की समझ ही नहीं होगी कि कांग्रेस का शासन कैसा था।

मूसे वाला के परिवार से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, भगवंत मान की सरकार से पूछा ये सवाल

चंडीगढ़। जेल से रिहा होने के बाद क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर

से एक्टिव पॉलिटिक्स में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने सिद्धू मूसे वाला के परिवार से मुलाकात की। पिछले साल सिद्धू मूसे वाला की हत्या कर दी गई थी। सिद्धू मूसे वाला के परिवार से मिलने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार किसी की भी हो पहली प्राथमिकता आम लोगों की रक्षा होनी चाहिए। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी हो सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि लोगों की जान की रक्षा करना। मैं पूछना चाहता हूं कि यहां की सरकार अपराध से रक्षा करती है या अपराध करती है? सिद्धू ने मूस वाला को कांग्रेस पार्टी में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और विधानसभा चुनावों के दौरान गायक के लिए प्रचार भी किया था।

हुड़दंग, नौटंकी, हंगामे से तामझाम तक, राहुल गांधी की याचिका पर भाजपा नेता का हमला

नई दिल्ली। मानहानि केस में दो साल की सजा के खिलाफ आज राहुल गांधी सूरत की सेशंस कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। सूत्रों के अनुसार, इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता रहेंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर अब भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे नौटंकी करार दिया और कहा कि ये सब लोग अपील के नाम पर हुड़दंग करने जा रहे हैं। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, राहुल गांधी अपने परिवार के सदस्य, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ सूरत जा रहे हैं। यहां वो कोर्ट द्वारा सुनाए गए दो साल की सजा के खिलाफ अपील के नाम पर हुड़दंग की कोशिश करेंगे। पात्रा ने आगे कांग्रेस और राहुल से सवाल किया कि क्या ये न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी को ओबीसी समाज के लोगों के लिए जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करने, ओबीसी समाज को अपमानित करने के लिए दोषी करार कर दंडित किया। उनकी सदस्यता रद्द हुई। ये कार्रवाई यूपीए सरकार के दौरान बनाए गए कानून के तहत ही हुई है।

समीक्षा

आसान नहीं कर्नाटक, बीजेपी-कांग्रेस में कलह के बीच जेडीएस की राह

उमेश चतुर्वेदी

टीवी चैनलों के दौर इस में बौद्धिकों की नजर में हर विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल बन गया है। विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित होते ही विशेषकर राजधानी केंद्रित बौद्धिक घोषित करने लगते हैं कि आने वाले चुनावों पर इस चुनाव विशेष के नतीजों का बड़ा असर होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भी ऐसी ही स्थापित धारणाएं लगातार प्रसारित हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के उभार के बाद ऐसी धारणाएं कई बार ध्वस्त हुई हैं। फिर भी इन्हीं धारणाओं के इर्द-गिर्द कर्नाटक के संभावित नतीजों का आकलन किया जा रहा है।

कर्नाटक के अतीत के अनुभव भी इन स्थापित धारणाओं को खारिज करते रहे हैं।

याद कीजिए 1999 के विधानसभा चुनाव को। तब जनता दल के जेएच पटेल मुख्यमंत्री थे। आम धारणा थी कि येदियुरप्पा की अगुआई में दक्षिण के इस राज्य में अपने दम पर कमल खिल जाएगा। लेकिन कमल खिलने के पहले ही मुरझा गया। वजह बनी बीजेपी की अगुआई वाली केंद्र सरकार की सेहत। तब 24 दलों के गठबंधन की सरकार चला रही बीजेपी के लिए जेएच पटेल मजबूरी बन गए। केंद्र में जॉर्ज फर्नांडिस की अगुआई वाले जनता दल के धड़ों का एकीकरण हुआ। जॉर्ज एनडीए के संयोजक थे, लिहाजा उनकी बात काटना बीजेपी के लिए संभव नहीं रहा। उसे जेएच पटेल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना पड़ा और कांग्रेस के भाग्य से छींका टूट गया।

2018 के चुनावों में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उत्साही टीवी चैनलों और चुनावी भविष्यवक्ताओं ने येदियुरप्पा की ताजपोशी करा दी। लेकिन 15 मई 2018 को घोषित नतीजों में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी ने सरकार तो बनाई, लेकिन येदियुरप्पा को बहुमत साबित किए बिना ही हटना पड़ा।

यह बात और है कि बाद में कांग्रेस और जेडीएस में सेंध के जरिए वह सत्ता की सीढ़ी चढ़ गए।

पिछले विधानसभा चुनाव परिणामों में ही इस बार का भी नतीजा छुपा है। पिछली बार कांग्रेस को बीजेपी से छह लाख 38 हजार 621 वोट ज्यादा मिले थे। फिर भी उसकी सीटें घट गईं। कारण रहा कर्नाटक केंद्रित पार्टी जनता दल-एस का प्रदर्शन। वह कई सीटों पर त्रिकोणात्मक संघर्ष बनाने में सफल रही। वैसे तो कर्नाटक तक ही जनता दल सेक्युलर का वजूद सिमटा है। विशेषकर वोक्कालिगा समुदाय में इस पार्टी का असर है, जो मुख्यतः मैसूर और दक्षिणी कर्नाटक में है। फिर भी वह चाहेगी कि किसी भी दल को बहुमत ना हासिल हो ताकि वह मोलभाव की स्थिति में रहे।

कर्नाटक में यूं तो मुस्लिम जनसंख्या दस फीसदी से कुछ ही ज्यादा है। लेकिन हाल के दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बने मुस्लिम नैरेटिव में कर्नाटक की भूमिका अहम रही। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हिजाब प्रकरण कर्नाटक की ही जमीन पर उभरा। हैरत की बात है कि जो राज्य कंप्यूटर क्रांति की जमीन बन चुका है, वहां हिजाब को लेकर बवाल हुआ। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार ने मुसलमानों को विशेष श्रेणी के तहत मिलने वाले 4 फीसदी का आरक्षण खत्म कर उसे वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों में बांटने की घोषणा कर दी। इन दोनों मसलों पर मुस्लिम समुदाय का संगठित होना स्वाभाविक है। ऐसे में कांग्रेस और जेडीएस का मुस्लिमों को लुभाना भी सहज है। दोनों चाहेंगे कि मुस्लिम समुदाय का एकमुश्त वोट उन्हें ही मिले।

इसी बिंदु से बीजेपी की उम्मीद भी जुड़ी है। हाल के दिनों में देखा गया है कि अगर मुस्लिम संगठित होता है तो उसके बरक्स हिंदू समुदाय भी अपनी पारंपरिक बिखराववादी सोच को दरकिनार करने की कोशिश करता है। बीजेपी अपनी अंदरूनी नीति के चलते सत्ता से अलग किए जा चुके येदियुरप्पा की लिंगायत समुदाय में पकड़ को भुनाने में जुट गई है। वह मोदी की लोकप्रियता, संगठित मुस्लिम के बरक्स हिंदू समाज की गोलबंदी और येदियुरप्पा के निजी असर के सहारे मैदान मारने की तैयारी में है। यह भी सच है कि सत्ता का अंदरूनी संघर्ष उसे झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस और जनता दल-एस से पाला बदलकर आए लोगों और पारंपरिक नेताओं की अंदरूनी खींचतान से वह जूझ रही है। हालांकि मोदी के नाम पर वह एकता और आगे बढ़ने का संदेश दे रही है।

वैसे गुटबाजी कांग्रेस में भी कम नहीं है। डीके शिवकुमार और पूर्व में देवेगौड़ा के सहयोगी रहे सिद्धारमैया के गुटों के अलावा पी परमेश्वर का भी गुट है। लेकिन पार्टी इन सभी गुटों को समायोजित करते हुए इनके नेताओं की उम्मीदवारी पहले ही घोषित कर चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कर्नाटक के ही हैं। उसे इन चुनावों में स बात का भी फायदा मिलने की उम्मीद है। दिलचस्प है कि इस बार कांग्रेस के रणनीतिकारों में दो ऐसे हैं, जो जनता दल के दिनों में पार्टी के युवा नेता के तौर पर प्रभावी रहे। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए जो कमिटी बनाई, उसके प्रमुख मोहन प्रकाश कांग्रेस में आने से पहले जनता दल में थे। जब वह युवा जनता दल के अध्यक्ष थे, तब सिद्धारमैया भी जनता दल का दक्षिण में युवा चेहरा थे। जाहिर है, इस बार दो पूर्व जनता दलियों पर कांग्रेस की नाव पार लगाने का दारोमदार है।

जनजाति समाज के धर्मांतरित व्यक्तियों को पृथक किया जाय : लता

डिलिस्टिंग को लेकर पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने नगरी में की बैठक, भाजपा पदाधिकारियों के अलावा जनजाति समाज के पदाधिकारी रहे मौजूद

नगरी। पूर्व मंत्री लता उसेंडी का नगरी आगमन हुआ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, जनजाति सुरक्षा मंच एवं जनजाति गौरव समाज के लोगों से चर्चा करते हुए कहा मतांतरण के कारण हमारा समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है। मतांतरण सभी समाज के लिए संकट है। डीलिस्टिंग के माध्यम से धर्मांतरण किये लोगों को शासन की जो सुविधा है शासन के संविधानिक अधिकार है उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। जनजाति समाज के धर्मांतरित व्यक्तियों को जनजाति समाज से पृथक किया जाय। आए दिन लोग मतांतरण कर रहे हैं जिससे वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है जिसे बचाने की आवश्यकता है, कानून बनाने की आवश्यकता है उन्होंने केंद्र सरकार से कानून में प्रावधान कर धर्मांतरण करने वालों को आरक्षण के साथ-साथ अन्य संवैधानिक अधिकार का लाभ न मिले ऐसा कानून बनाया जाए।

आगामी 16 अप्रैल को रायपुर में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया है। धमतरी जिले व नगरी सिहावा क्षेत्र से अधिक से अधिक जनजाति समाज के लोग रायपुर के कार्यक्रम में उपस्थित हो। इस अवसर पर नगरी सिहावा के पूर्व विधायक पिंकी शिवराज शाह एवं श्रवण मरकाम ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि धर्मांतरण से सांस्कृतिक दिक्कत

उत्पन्न हो रही है यह सभी समाज के लिए संकट की बात है समाज के विकास के लिए हम सब डिलिस्टिंग मुद्दे पर काम करने के लिए तैयार हैं।

बैठक में आम सहमति से धमतरी जिले के चारों विकासखंड के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया । जो अपने-अपने विकासखंड प्रभार में बैठक आयोजित कर 16 अप्रैल के आंदोलन हेतु सभी सामाजिक जनों को रायपुर कार्यक्रम हेतु तैयार करेंगे।

नगरी के प्रभारी- पिंकी शिवराज शाह जी, दिनेश्वरी-महेन्द्र नेताम, मोहन पुजारी जी, के एस शांडिल्य जी, प्रेमलता नागवंजशी, रामकुमार सामरथ, गौचंद मरकाम, बंशीलाल सोरी, ईश्वरी नेताम। मगरलोड के प्रभारी- श्रवण मरकाम, माधव सिंह ठाकुर जी, हीरामन ध्रुव, नारायण सिंह ध्रुव। धमतरी प्रभारी- श्यामलाल नेताम (पार्षद), रामखिलावन कंवर जी, खूबलाल ध्रुव, रामेश्वर मरकाम, शिव नेताम, दिग्विजय ध्रुव, कमलनारायण ध्रुव। कुरूद प्रभारी- झगेश्वर ध्रुव, दुलेश्वर ध्रुव, चित्रसेन ध्रुव भखारा, मिलाप ध्रुव मेघा, प्रहलाद ध्रुव सिर्री बनाये गये हैं।

इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष दिनेश्वरी नेताम जी, नगर पंचायत अध्यक्ष आराधना शुक्ला जी, अजजा मोर्चा जिला अध्यक्ष महेंद्र नेताम, जिलामंत्री प्रेमलता नागवंशी, सरपंच ईश्वरी नेताम, जिला महामंत्री प्रकाश बैस, नगरी मंडल अध्यक्ष मोहन नाहटा, बेलर मंडल अध्यक्ष अकबर कश्यप, कुकरेल मंडल प्रभारी विकल गुप्ता, जिला मंत्री राजेंद्र गोलछा, नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र शुक्ला, अजजा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र नाग, नागेंद्र बोर्झा, अजय ध्रुव, जनपद सभापति सुलोचना साहू, प्रतिमा देवांगन, संत कोठारी विहिप, महामंत्री हृदय साहू, मीडिया प्रभारी राम गोपाल साहू, युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी निखिल साहू, महामंत्री राजेश गोसाईं, मंडल मंत्री बलजीत छाबड़ा, उप सरपंच नरसिंह मरकाम, सभापति व युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील निर्मलकर, पार्षद अश्विनी निषाद, सरपंच विमला धुर्वा, अनीता मरकाम, नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा राजा पवार, नरेश गायकवाड़, गज्जू शर्मा, मनीष शर्मा, द्रविड़ नाग, यशवंत साहू, विकास जैन उपस्थित थे।

पूर्व मंत्री लता उसेंडी सचिव संघ के मांगों का समर्थन करने पहुंचीं

नगरी। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रावण भाठा नगरी में किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य सुश्री लता उसेंडी एवं राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा एवं पूर्व विधायक श्रीमती पिंकी शिवराज शाह इस आंदोलन के समर्थन में रावणभाठा नगरी स्थित धरना स्थल पर पहुंचे।इस दौरान सुश्री लता उसेंडी ने कहा कि यह सरकार गंगाजल की कसम खाकर हर वादों से मुकर रही है।यह सरकार पूरी तरह से अहंकार में चल रही है।इन्होंने सरकार बनने से पहले गंगाजल लेकर के यह वादा किया था कि सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जावेगा। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि अब यह सरकार किसी भी आंदोलनरत अधिकारी कर्मचारियों से बात करने को तैयार नहीं है।इससे ऐसा लगता है कि यह सरकार अहंकारी हो गई है।श्रीमती पिंकी शिवराज शाह ने कहा कि सरकार को अपने द्वारा किए गए वादा को पूरा करना चाहिए। अपने वादों से मुकरना नहीं चाहिए।झुठे वादों के चलते यह सरकार बनी है आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस दौरान सचिव संघ ने भाजपा नेताओं का अभिनंदन स्वागत किया इस समर्थन पर उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला के मंत्री राजेंद्र गोलछा श्रीमती प्रेमलता नागवंशी मंडल अध्यक्ष मोहन नाहटा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ डॉक्टर के एस शांडिल्य,जनपद अध्यक्ष दिनेश्वरी नेताम,जिला अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष एवं सरपंच महेंद्र नेताम,महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सुलोचना साहू, कुकरेल मंडल के महिला मोर्चा के अध्यक्ष ईश्वरी नेताम, निर्गुड़ी की सरपंच अनिता सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

लता उसेंडी गोलछा निवास पहुंचीं

नगरी। छत्तीसगढ़ शासन में पूर्व मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य कोंडागांव से पूर्व विधायक सुश्री लता उसेंडी नगरी आगमन के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं जिला मंत्री राजेंद्र गोलछा के निवास पहुंच सौजन्य भेंट की। इस दौरान राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा एवं पूर्व विधायक पिंकी शिवराज शाह,जिला मंत्री भाजपा प्रेमलता नागवंशी,महिला मोर्चा अध्यक्ष सुलोचना साहू,बेलर मंडल के अध्यक्ष अकबर कश्यप उपस्थित रहे।

बैगा जनजाति ने राष्ट्रपति को दी बिरनमाला

छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया : मुर्मू

कबीरधाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कबीरधाम जिले की महिला स्व सहायता समूह की 10 सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। सदस्यों में शामिल विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति की महिलाओं ने राष्ट्रपति को बिरन माला भेंट की। इस पर राष्ट्रपति ने कहा, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। महिला स्व सहयता समूह के सदस्यों के लिए 28 मार्च से 31 मार्च तक अमृत उद्यान दर्शन के लिए खोला गया था। इसमें 31 मार्च को स्व सहायता समूह विशेषकर आदिवासी, विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया था।

कबीरधाम से गईं महिला समूह की सदस्यों ने अमृत उद्यान का भ्रमण करते हुए राष्ट्रपति से मुलाकात की। कबीरधाम जिले से पंडरिया विकासखंड के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय की धनमत, दशमी बाई, लक्ष्मीया, इंद्रावती, रामकली, फूलबत्ती, चंपा बैगा, बिंदा, पार्वती और सावनी बाई मौजूद रहीं। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने बताया कि राज्य शासन से प्राप्त निर्देशानुसार जिले अंतर्गत कार्यरत स्व-सहायता समूह के सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान दर्शन के लिए भेजा गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि, सभी महिलाएं विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय से हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर अच्छा कार्य कर रही हैं। महिलाओं को सुगमता पूर्वक जिले से लाने व ले जाने के लिए जिला स्तर पर जय कैवर्थ एवं ब्लॉक स्तर के लिए सविता यादव नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। कबीरधाम जिले के सात राज्य के अन्य दो जिले की महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुई है।

बिलासपुर हाईकोर्ट का स्वास्थ्य मंत्री को नोटिस

बांध की जमीन बेचने का आरोप, सिंहदेव बोले- एनजीटी खारिज कर चुकी

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। उन पर अंबिकापुर के सत्तीपारा स्थित बांध मद की जमीन को बेचने का आरोप है। कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री को 11 अप्रैल को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जल संरक्षण एवं पर्यावरण के लिए कार्य करने वाली संस्था तरु नीर समिति की ओर से याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की बेंच में हुई है। वहीं सिंहदेव का कहना है कि एनजीटी पहले ही मामले को खारिज कर चुकी है।

मामला अंबिकापुर शहर के मध्य स्थित मौलवी बांध के 52 एकड़ जमीन का है। सरगुजा राजपरिवार की वो जमीन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नाम पर है। इसका खसरा नंबर 3467 रकबा 52.06 एकड़ का है। अंबिकापुर की तरू नीर समिति ने 20 मार्च को उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया है कि, तालाब को टीएस सिंहदेव की ओर से पाट कर जल क्षेत्र को बंद किया जा रहा है। उक्त भूमि में से 128 व्यक्तियों को टुकड़ों-टुकड़ों में तालाब की भूमि को करोड़ों रुपए में बेचा जा रहा है।

11 अप्रैल को प्रस्तुत करना होगा जवाब

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चन्द्रवंशी के बेंच ने याचिका की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिहंदेव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि टीएस सिंहदेव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या फिर अपने वकील के माध्यम से 11 अप्रैल को अपना जवाब प्रस्तुत करें। यदि आपकी ओर से 11 अप्रैल को अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो याचिका की सुनवाई करते हुए एकतरफा निर्णय लिया जाएगा।

तरू नीर समिति ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि शिवसागर तालाब व मौलवी बांध जो सेटलमेंट रिकार्ड में सार्वजनिक निस्तार के जलस्रोत के मद के रूप में रकबा 52 एकड़ दर्ज है। जल स्रोत आजादी के बाद राजपरिवार के नाम दर्ज हुई थी। नवंबर 1996 को सरगुजा कलेक्टर ने यह बताते हुए कि 21 एकड़ में जलस्रोत है शेष 33.18 भूमि को आवासीय व व्यवसायिक मद में बदल दिया। कलेक्टर द्वारा लैंडयूज बदले के बाद तालाब में निर्माण सामाग्री पाटी गई और भवन व अन्य निर्माण कार्य कराए गए। कोलोनाइजर द्वारा यहां कालोनी का निर्माण कराया गया है।

वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, शिव सागर बांध का जो एरिया है ये उनकी पुश्तैनी जमीन है। वो 1947 में भारत सरकार और सरगुजा राजपरिवार के बीच हुई संधि में उल्लेखित है। 2017 में इस जमीन की शिकायत तरु नीर समिति ने राज्य सरकार से की थी। तब तत्कालीन कलेक्टर ने शिकायत खरिज करते हुए रिपोर्ट राज्य सरकार को दी थी। वर्ष 2018 में आलोक दुबे ने एनजीटी में याचिका दर्ज की। इसमें तरु नीर की शिकायत का भी उल्लेख किया। वर्ष 2019 में एनजीटी ने इस मामले को खारिज किया और भूमि के विवाद पर पूर्ण विराम लगाया।

सिंहदेव ने कहा कि, मीडिया के साथियों के माध्यम से उनको जानकारी मिली है कि फिर से तरु नीर ने मुझे शिव सागर बांध के मामले में पार्टी बनाने के लिए उच्च न्यायालय के सामने मांग की है। ये नोटिस अभी तक मुझे प्राप्त नही हुआ है। मीडिया के साथियों के द्वारा भेजे गए दस्तावेज का अध्ययन कर यह प्रतीत होता है कि न्यायालय ने मुझे ऐसा कहा है कि मामले में तरु नीर समिति ने आपको पक्ष बनाने की मांग की है। अभी न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, तो तथ्यों पर कुछ कहना उचित नही होगा, लेकिन इस मामले की पृष्ठभूमि से ये साफ है कि कौन लोग और किस उद्देश्य से बार बार इस मामले को उठाते हैं।

रावघाट-जगदलपुर रेललाईन जल्द शुरू नहीं हुआ तो बस्तर बंद का अल्टीमेटम

जगदलपुर। बस्तर रेल आंदोलन की पदयात्रा के एक वर्ष बाद आयोजित बैठक में रावघाट-जगदलपुर रेल के मुद्दे पर शामिल वक्ताओं ने विचार रखे। रेलबजट में रावघाट-जगदलपुर में बजट मिलने की जानकारी पर भी चर्चा की गई जिस पर सबने यही कहा कि रावघाट जगदलपुर का रेल बजट कागजी साबित हो रहा है, रावघाट-जगदलपुर बजट फाइल धूल खा रही है। बस्तर की उपेक्षा से अब बस्तरवासियों में जनाक्रोश बढ़ रहा है। वक्ताओं ने जनप्रतिनिधियों की उदासीनता पर आक्रोश व्यक्त किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि रावघाट-जगदलपुर यात्री रेल लाइन को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग को लेकर रायपुर डीआरएम को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद भी रावघाट-जगदलपुर रेललाइन का कार्य जल्द शुरू नहीं हुआ तो बस्तर बंद करते हुए रेल आंदोलन को आगे बढ़या जायेगा।

बैठक में बस्तर रेल आंदोलन के संतोष जैन, मनीष शर्मा, दशरथ कश्यप, संपत झा, विमल बोथरा, चन्देश चांडक, शिव चांडक, उमा झा, रूपेश झा राजेंद्र सिंह, राजकुमार दण्डवानी, शंकरलाल गुप्ता, रोहित सिंह बेस, पुरुषोत्तम नोयल, हेमंत कश्यप, योगेंद्र कौशिक, सुरेश यादव, कौशल नागवंशी, टी के शर्मा, सुभाष राय, विपिन जोबनपुत्रा, ज्योति गर्ग, गाजिया अंजुम, हेमा गुरुवारा सहित बस्तर बस्तर चैबर आफ कामर्स के सदस्यों सहित विभिन्न सामाजिक संघ संगठन शामिल थे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सरपंच व ग्रामीण की हत्या में शामिल 2 नक्सली गिरफ्तार

दंतेवाड़ा। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत डीआरजी के जवान नक्सल गश्त सर्चिंग में थाना कुआकोण्डा के ग्राम एटेपाल बिलईपारा की ओर रवाना हुये थे, ग्राम ऐटेपाल के जंगल से नक्सलियों के जियाकोड़ता पंचायत जनताना सरकार उपाध्यक्ष हिड़मा उर्फ बोटी माड़वी जाति माडिया़ निवासी ऐटेपाल बिलईपारा थाना कुआकोण्डा एवं नक्सलियों के ग्राम एटेपाल डीएएमएस सदस्य नंदा माड़वी पिता स्व. हुर्रा माड़वी जाति माडिया़ निवासी एटेपाल आसूपारा थाना कुआकोण्डा गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली हिड़मा उर्फ बोटी माड़वी 9 नवंबर 2021 को गोपनीय सैनिक उमेश मरकाम की हत्या में शामिल था, इसके अलावा थाना कटेकल्याण में पूर्व से आधा दर्जन से ज्यादा अपराध पंजीबद्ध होने पर कर्यवाही उपरांत आज न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। गिरफ्तार नक्सली डीएएमएस सदस्य नंदा माड़वी ग्राम पंचायत छोटेगुडरा केसरपंच लखमा मण्डावी एवं ग्रामीण लक्ष्मण मण्डावी की हत्या में शामिल था।

दर्री पुलिस पर पैसे मांगने का आरोप, चौकी के सामने हंगामा

कोरबा। सीएसईबी पुलिस चौकी के पास एक व्यक्ति ने दर्री पुलिस पर पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए सड़क पर हंगामा किया। उसका कहना था कि दर्री पुलिस ने चोरी के आरोप में उसके बेटे को हिरासत में लेकर अपराध कबूल करवाने बुरी तरह पिटाई कर रही है। 30 हजार रुपये मांगने का आरोप पुलिस पर लगाते हुए कहा कि पैसा मिलने के बाद ही बेटे को छोड़े की बात पुलिस कह रही है। सीएसईबी चौकी के पास एक कार में राजकुमार नेताम नामक एक व्यक्ति टावेल में गाडी से नीचे उतरा और हंगामा करने लगा। कार को सड़क के बीच में खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो गया और लोगों की भीड़ लग गई। सीएसईबी पुलिस चौकी में उपस्थित कर्मी भी बाहर निकले और उसके हंगामा करने की वजह पूछी। तब उसने अपना नाम राजकुमार नेताम बताया और कहा कि मेरे नाबालिग बेटे को दर्री पुलिस ने चोरी के आरोप में पकड़ लिया है और अब उसे छोड़ने के लिए रुपयों की मांग की जा रही। मैने कहा कि इतने पैसे अभी मेरे पास नही है।

हिर्री ग्राम पंचायत की सरपंच को एसडीएम ने किया बर्खास्त

जांजगीर। पामगढ़ जनपद पंचायत के हिर्री ग्राम पंचायत की सरपंच शारदा ज्योति को एसडीएम आरके तंबोली ने बर्खास्त कर दिया है। उसके खिलाफ 14 और 15वें वित्त की राशि में घोटाले का आरोप लगा था, जिसे जांच में सही पाया गया। सरपंच पर कार्रवाई पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) और 40 (2) के तहत की गई है। शिकायत की जांच के बाद सामने आया कि सरपंच ने 1.10 लाख रुपए का पैरा खरीदने के नाम पर आहरण किया था, जबकि कोई खरीदी नहीं की गई। इसी तरह बाजार में ट्यूबवेल खुदाई के लिए 75 हजार रुपए निकाले गए थे। उसने किसी दूसरे स्थान की फर्जी फोटो लगाकर राशि निकाली थी जबकि बताई गई जगह पर कोई खुदाई नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सभी पंचों ने उक्त सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था लेकिन कुछ पंचों को उसने अपनी तरफ मिला लिया था। इसके पहले पामगढ़ के सरपंच तेरस यादव को भी एसडीएम करुण डहरिया ने बर्खास्त किया था।

ग्राम पंचायत हरवेल के ग्रामों में मनाया गया माटी त्योहार

नारायणपुर। बड़ेराजपुर ब्लाक अंर्तगत ग्राम पंचायत हरवेल के ग्राम तरईबेड़ा, डीहीपारा, कुल्दाडीही, पीढापाल, पिटीसपाल, धामनपुरी, किबड़ा गम्हरी, बालेंगा, राहटीपारा, तितरखंड,जोडेकेरा, बडबत्तर, जामपारा, छिंदली, कोपरा, में ग्राम हरवेल के पुजारी रामलाल मंडावी, गायता मंगतर मंडावी, ग्राम पटेल लच्छिमनाथ मंडावी एवं ग्राम के सियान बुजुर्ग युवा ग्रामीणों के मौजूदगी में माटी त्योहार परंपरानुसार मनाया गया है। बस्तर के ग्रामीण परंपरानुसार माटी त्योहार अच्छी फसल के लिए कृषि भूमि की पूजा कर मनाते हैं। यह पर्व अलग-अलग ग्रामों में स्थानिय देवगुड़ी के पुजारी ग्राम पटेल एवं ग्रामीणों के द्वारा तय किये गये दिन में मनाया जाता है। माटी त्योहार के दिन ग्रामीण मिट्टी से सम्बंधित किसी प्रकार से कोई भी कार्य जैसे मिट्टी खोदना, खेतों में हल चलाना आदि नहीं करते हैं। यदि कोई नियम विरुद्ध कार्य करते पाया गया तो समुदाय द्वारा उस व्यक्ति को दण्डित भी किया जाता है।

मेकॉज में 35 बेड का कोरोना वार्ड बनाया

जगदलपुर। बस्तर संभाग में कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से दिशा निर्देश जारी किये गए हैं। इसे देखते हुए मेडिकल कॉलेज में एतिहात के तौर पर तैयारियां शुरू करते हुए एक अलग से वार्ड तैयार कर दिया गया है। मेकॉज प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक 35 बेड का कोरोना वार्ड तैयार कर दिया गया है, इससे छह गुना ज्यादा बेड आपातकालीन समय में रिजर्व में रखे गए हैं। यानी किसी भी आपातकालीन स्थिति में 35 बेड को 200 बेड में तब्दील किया जा सकता है। कोरोना के नए वैरिएंट की पहचान के लिए जिन मरीजों के सैंपलों में अंदेशा रहता है, उसे जीनोम सिक्वेसिंग के लिए भुनेश्वर या रायपुर भेजा जाता है। कई बार पूणे भी सैंपल भेजना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि अब तक कोरोना व अन्य वायरस के बस्तर में मिलने की जानकारी नहीं मिली है। मेकॉज अधीक्षक डॉ. अनुरूप साहू ने बताया भारत सरकार के गाइड लाइन के हिसाब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बार 35 बिस्तरों का कोविड वार्ड बनाया गया है।

वरिष्ठ राजनेता स्व. बिसाहूदास महंत पर केन्द्रित स्मारिका का विमोचन

■ **बड़ी संख्या में साहित्यकार ,पत्रकार , जन प्रतिनिधि और नागरिक हुए शामिल**

जांजगीर। स्व.बिसाहू दास महंत स्मृति आयोजन समिति जांजगीर और छत्तीसगढ़ साहित्य एवं संस्कृति संस्थान रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में जिला मुख्यालय जांजगीर के बीडीएम बालोद्यान में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ राजनेता, पूर्व विधायक एवं मध्यप्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय बिसाहूदास महंत जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में साहित्यकारों ,पत्रकारों और प्रबुद्धजनों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ ही स्वर्गीय श्री महंत के जन्मशताब्दी वर्ष की भी शुरुआत हुई। ज्ञातव्य है कि स्वर्गीय श्री बिसाहूदास महंत तत्कालीन अविभाजित मध्यप्रदेश की विधानसभा में छह बार

विधायक रह चुके थे। उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में भी अपने सार्वजनिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया ।

उनकी स्मृति में जांजगीर में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने राजधानी रायपुर के साहित्यकार राम पटवा द्वारा सम्पादित स्मारिका 'कबीर परंपरा के संत राजनेता बिसाहूदास महंत' का विमोचन किया । समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने की । कार्यक्रम में कोरबा की लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महन्त , छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजर्षि महन्त रामसुन्दर दास, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ अरब शाकम्बरी बोर्ड के अध्यक्ष श्री पटेल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सभी वक्ताओं ने स्वर्गीय श्री बिसाहूदास महंत के सहज -सरल व्यक्तित्व और छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश के विकास में उनके योगदान को याद किया। समारोह में बड़ी संख्या में साहित्यकार ,पत्रकार और जांजगीर, सक्ति , कोरबा , बिलासपुर , रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आए साहित्यकार और जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध नागरिक शामिल हुए।

उल्लेखनीय है कि विमोचित स्मारिका 'कबीर परंपरा के संत राजनेता बिसाहूदास महंत' स्वर्गीय बिसाहूदास महंत के पारिवारिक , राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का संक्षिप्त दस्तावेज़ है । विमोचन समारोह में छत्तीसगढ़ साहित्य एवं संस्कृति संस्थान रायपुर के अध्यक्ष डॉ.सुशील त्रिवेदी सहित डॉ एल.एस. निगम ,डॉ . चित्तरंजन कर,अजय तिवारी , डॉ. सुधीर शर्मा, दिवाकर मुक्तिबोध ,आशीष ठाकुर ,अरविन्द मिश्रा, जयप्रकाश मानस , डॉ . माणिक विश्वकर्मा 'नवरंग', राम पटवा देवाशीष मुखर्जी, डॉ सुरेश शुक्ला तथा जांजगीर के विजय दुबे ,विजय राठौर और सतीश सिंह भी मौजूद थे।

बेरोजगारी भत्ता के नाम पर भूपेश बेरोजगारों को झुनझुना दिखाने का काम कर रही है: मनोहर

नगरी। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को सरकार ने बेरोजगारी भत्त्ता देने की घोषणा की है। सरकार की तरफ से बेरोजगार तय करने के लिए नियम बनाए गए, जिस पर भाजपा ने आपत्त्ति की है।भाजपा मण्डल बेलर के महामंत्री मनोहरदास मानिकपुरी ने सरकार से पूछा कि जब सब लोग अपात्र हो जाएंगे, तो भत्त्ता किसे दिया जाएगा । मानिकपुरी ने कहा कि भूपेश सरकार बेरोजगार युवाओं को केवल गुमराह व छलने का काम कर रही है। 2018 में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के 10 लाख युवाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की थी, जो अब तक अधूरी है।

विदित हो कि भत्त्ता के लिए पिछले चार वर्षों में कांग्रेस ने केवल समितियां बनाकर बैठकें की। अब उनको चुनाव देखकर बेरोजगारी भत्ता याद आ रहा है। मानिकपुरी ने आरोप लगाया कि पिछले 51 महीने तक युवाओं को 2500 रुपये भत्ता नहीं दिया गया। क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ आखिरी छह महीने के लिए ही था?मानिकपुरी ने कहा सरकार ने बेरोजगारी भत्ता के लिये जो नियम बनाया है, उसमें परिवार का कोई भी व्यक्ति निजी या सरकारी नौकरी में है वह परिवार का युवा बेरोजगारी भत्ता के पात्र नहीं है। पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि या समर्थन मूल्य पर 75 क्विंटल धान बेचने वाले परिवार के बेरोजगार युवा भी पात्र नहीं हैं। यह सब नियमों से स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के नाम पर केवल झुनझुना दिखाने का काम कर रही है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

कर्नाटक में टिकट के लिए कांग्रेस नेताओं का हंगामा

बेंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। इसके साथ ही टिकट पाने के लिए पार्टी नेताओं की दावेदारी भी शुरू हो गई है। सोमवार को बेंगलुरु स्थित कांग्रेस मुख्यालय में टिकट की मांग को लेकर खूब हंगामा हुआ। दरअसल कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता टिकट की मांग लेकर बेंगलुरु स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि सर्वे के बाद ही उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। बता दें कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी भी कर चुकी है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के टिकट की मांग के बीच कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने बताया कि हमारे टिकटों की भारी मांग है। मंगलवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में टिकट पाने वाले उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। हमने सर्वे कराए हैं और जो भी सबसे अच्छा उम्मीदवार होगा, उसे टिकट दी जाएगी।

चाय के निमंत्रण पर केजरीवाल पर हिमंत सरमा का पलटवार

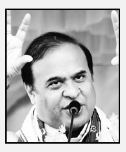

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत सरमा ने अपने दिल्ली के समकक्ष अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय राजधानी में अपने निवास पर चाय और दोपहर के भोजन के निमंत्रण का जवाब दिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख को कायर कहा, जिनकी वीरता विधानसभा के भीतर ही सीमित है। केजरीवाल के चाय के निमंत्रण का जवाब देते हुए, हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, हम अपने मेहमानों को भगवान के रूप में मानते हैं। लेकिन जब औरंगज़ेब असम आया, तो लचित बरफुकन ने उसे कोई आतिथ्य प्रदान नहीं किया। अब, जब आप असम में झूठ बोलने आते हैं, तो हम क्यों विचार करें। आप मेहमान? फिर भी मैंने आपको सुरक्षा दी, जो आप नहीं करते। कोविड के दौरान मैंने कई बार ट्वीट किया, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। कृपया हमें अकेला छोड़ दो। हमें आम आदमी बनने की जरूरत नहीं है, हम खास आदमी रहेंगे। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश में कहा, असम विकास के रास्ते पर चल रहा है।

ममता सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन

कोलकाता। रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुए बवाल को लेकर राजनीति जबरदस्त तरीके से जारी है। भाजपा पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता हर जगह जाएंगे और घायलों से मिलने की कोशिश करेंगे। हमने केंद्रीय बल की तैनाती और एनआईए द्वारा जांच की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि ऐसी कौन सी धारा 144 है जिसमें बम चल रहे हैं। यहां के सांसद और चेयरमैन 144 में घूम रहे हैं। उनके लिए धारा 144 नहीं है? भाजपा महासचिव लॉकेट चटर्जी ने कहा कि मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने सबको खुला छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ रामनवमी पर ही नहीं बल्कि दुर्गा विसर्जन, सरस्वती पूजा शोभायात्रा पर हमला होता है। हम एनआईए द्वारा जांच की मांग करते हैं।

सिसोदिया को सीबीआई मामले में 17 तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

नईदिल्ली। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल, 2023 तक के लिए बढ़ा दी है। यह न्यायिक हिरासत सीबीआई के मामले में है। इससे पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। यह देखते हुए आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए आबकारी नीति मामले में शुक्रवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने इसके साथ ही कहा कि सिसोदिया प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार थे ।

भाजपा विधायकों ने मांगा नीतीश कुमार का इस्तीफा

पटना। बिहार के 2 शहरों में रामनवमी के बाद हुई हिंसा को लेकर राजनीति जबरदस्त तरीके से जारी है। दोनों ही मामलों को लेकर भाजपा नीतीश कुमार और उनके सरकार को घेर रही है। सोमवार को बिहार विधानसभा में पूरा मुद्दा उठा। भाजपा पूरे मामले को लेकर काफी आक्रमक है और कानून और व्यवस्था विफल होने की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने यह मुद्दा उठाया। हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भाजपा ने कई बड़े आरोप भी लगाए। भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में एक बार फिर से जंगलराज रिटर्न आ चुका है। आपको बता दें कि बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी के दिन विभिन्न कारणों से हिंसा भड़क गई थी। 4 दिनों के बाद भी फिलहाल वहां स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर आपात बैठक बुलाई थी।

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पांच अप्रैल तक स्थगित

राज्यसभा में हंगामे के बीच पारित हुआ विधेयक

, लोकसभा में भी नहीं चल सकी कार्यवाही

नईदिल्ली। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। लेकिन दोनों सदनों में हंगामे की वजह से अब तक कामकाज नहीं हो सके हैं। शुरुआत से ही संसद के दोनों सदनों में जो हंगामा देखने को मिला वह सोमवार को भी जारी रहा। हंगामें की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पांच अप्रैल तक स्थगित कर दी गई है। हंगामे के बीच ही राज्यसभा ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक को बिना चर्चा के ही मंजूरी दे दी। भाजपा सांसद जहां राहुल गांधी को लेकर विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से निशाना साध रहे हैं। तो वहीं विपक्षी दल अडानी मुद्दे पर सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने आज भी अडानी मामले में जेपीसी की मांग की और नारे लगाए। दोनों ही सदनों में सभापति की ओर से सदन को चलाने की कोशिश की गई। हालांकि, हंगामा कम नहीं हुआ जिसके बाद सदन की बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा।

राज्यसभा की कार्यवाही

हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। अपराह्न दो बजे जैसे ही सदन

की कार्यवाही दोबारा आरंभ हुई, सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को राज्यसभा दिवस की शुभकामनाएं दीं और कहा कि सदन चर्चा, बहस और विचार विमर्श के लिए है ना कि व्यवधान और हंगामे के लिए। राज्यसभा में हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, 2022' पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने अडाणी मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच हीइस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। 'प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, 2022' गत सप्ताह लोकसभा से पारित हुआ था। पिछले वर्ष अगस्त में निचले सदन में इसे पेश किया गया था। सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे सहित कांग्रेस के कई सदस्य काले कपड़े पहन कर सदन में आए थे। कुछ सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर की गई उनकी टिप्पणी के लिए माफी की मांग को लेकर नारे लगाए।

लोकसभा की कार्यवाही

अडाणी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजकर पांच मिनट पर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे बैठक शुरू हुई तो पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने आवश्यक दस्तावेज सभापटल पर प्रस्तुत कराए। इस दौरान कांग्रेस समेत विपक्ष के सदस्य आसन के पास आकर 'हमें चाहिए जेपीसी' के नारे लगाने लगे। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक करीब पांच मिनट बाद ही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले 11 बजे बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने अपने वर्तमान सदस्य गिरीश भालचंद्र बापट और पूर्व सदस्य इनोसेंट को श्रद्धांजलि दी जिनका पिछले दिनों निधन हो गया।

देश के लिए लड़ रहे हैं राहुल, कांग्रेस नेता उनके समर्थन के लिए पहुंच रहे : खड़गे

नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी देश के लिए, लड़ रहे हैं और ऐसे में पार्टी के नेता उनके समर्थन के लिए सूरत पहुंच रहे हैं तथा यह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने किसी को बुलाया नहीं है और जो भी नेता सूरत पहुंच रहे हैं वो उनका निर्णय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सोमवार को सूरत की एक अदालत में मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी वाद्रा, कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य राष्ट्रीय नेता और राज्य इकाइयों के नेता अदालत तक उनके साथ जा सकते हैं।

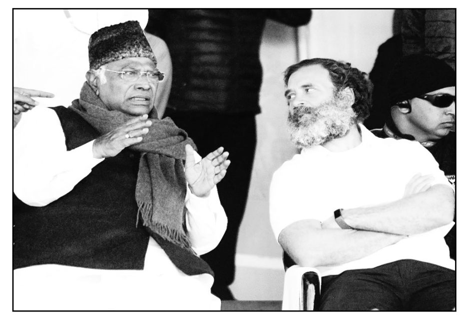

भाजपा का अलोकतांत्रिक चेहरा बार-बार बेनकाब हो रहा है। कांग्रेस इन सब हरकतों की निंदा करते हुए उनकी तुरंत रिहाई की मांग करती है।

खड़गे ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ''यह (नेताओं का सूरत पहुंचना) शक्ति प्रदर्शन नहीं है। राहुल जी हमारे नेता हैं तो नेता के साथ खड़े होने के लिए सभी जाते हैं। जब किसी के खिलाफ मामला होता है तो परिवार के लोग जाते हैं। यह तो पार्टी है और राहुल देश के लिए लड़ रहे हैं। हमारे लोग वहां पहुंच रहे हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं।'' उनका कहना था, ''यह पार्टी के लोगों का निर्णय है, उन्होंने (राहुल) किसी को नहीं बुलाया है।'' कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''अदालत के निर्णय पर हम बहस नहीं कर सकते। हम अन्याय के खिलाफ तो लड़ सकते हैं। हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अडाणी घोटाले को लेकर सरकार नहीं चाहती है कि जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) की जांच हो।

इस मांग को टालने की कोशिश हो रही है। सरकार यह तय करके आती है और सदन को स्थगित करवा देती है।'' कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि सूरत जाने वाले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की 'अवैध गिरफ्तारी' की जा रही है। उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया, ''गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं को सूरत जाने से रोकने के लिए अवैध गिरफ्तारी करने के समाचार लगातार मिल रहे हैं।

राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक मिली जमानत

सूरत। मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाले मामले की अगली सुनवाई 3 मई को सूरत की अदालत में होगी। इसके साथ ही राहुल गांधी की जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। कांग्रेस के पूर्व लोकसभा सांसद राहुल गांधी सोमवार को गुजरात के सूरत में एक निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत में अपील दायर करने पहुंचे थे। सूरत की एक निचली अदालत ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दोषी पाया था। एकजुटता दिखाने के लिए प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता, तीन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य राष्ट्रीय और राज्य पार्टी के नेता राहुल के साथ सूरत कोर्ट में मौजूद रहे। 24 मार्च को, शहर की एक निचली अदालत द्वारा राहुल गांधी को भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर एक मामले में दोषी पाया गया था। इसके बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को एक नियम के तहत लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा रोड़ा : प्रधानमंत्री

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) की डायमंड जुबली कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार, गरीब से उसका हक छीनता है, अनेक अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार, लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 दशक में सीबीआई ने बहु आयामी और बहु अनुशासनिक जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, आज सीबीआई का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। महानगर से लेकर जंगल तक सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है।

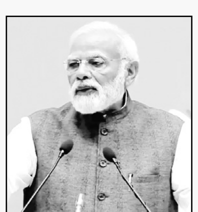

मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि आज नए कार्यालयों का शुभारंभ सीबीआई को कार्य करने में और सहायता प्रदान करेगा। सीबीआई की जांच की मांग के लिए तो आंदोलन तक किए जाते हैं, लोग कहते हैं कि मामले को सीबीआई को दे दें। न्याय, इंसाफ के ब्रैंड के तौर सीबीआई का नाम सबकी जुबान पर है। जिन्होंने भी सीबीआई में योगदान दिया वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्यजन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं कि इसे सीबीआई को दे देना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां भ्रष्टाचार होता है, वहां युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता-फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई-भतीजावाद, परिवारवाद को बल मिलता है। उन्होंने कहा कि जब भाई-भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है, तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है। जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास प्रभावित होता है।

खेल
प्रमुख समाचार

मेसी के लिए बार्सिलोना को लेनी पड़ रही अतिरिक्त मदद, कम पड़ रहा फंड

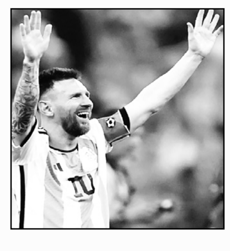

पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि लियोनेल मेसी अपने पुराने क्लब बार्सिलोना एफसी वर्तमान में वापसी कर सकते हैं क्योंकि उनकी टीम उन्हें वापस लाने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। इसे संबंध में बार्सिलोना एफसी की टीम खास तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इस बड़ी डील को जल्द ही सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अफवाहों की पुष्टि करते हुए, बार्सिलोना एफसी के उपाध्यक्ष राफा युस्ते ने शुक्रवार को पुष्टि की कि क्लब लियोनेल मेस्सी के साथ बातचीत कर रहा है कि उन्हें वापस लाया जा सके। वर्ष 2022 फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना को जीत दिलाने वाले स्टार खिलाड़ी को फिर से साइन करने की संभावना भी तलाश की जा रही है।युस्ते ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अभी भी सम्मान है। मेस्सी एक बार फिर से स्पेनिश लीग में बार्सिलोना के लिए खेलने का विकल्प तलाश रहे हैं। लियोनेल मेसी ने 2021 में पीएसजी के लिए, बार्सिलोना छोड़ दिया था। वहीं फ्रेंच लीग टीम के साथ अनुबंध जल्द ही समाप्त होने वाला है। बता दें कि मेस्सी ने 2021 में बार्सिलोना छोड़ दिया था क्योंकि क्लब उनके अनुबंध को नवीनीकृत करने का जोखिम नहीं उठा सकता था।

उन्होंने जल्द ही पीएसजी के स्टार खिलाड़ियों में से एक के रूप में सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दीं और 2022 फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना को फ्रांस के खिलाफ शानदार जीत दिलाने के बाद शीर्ष पर पहुंच गए। जबकि मेसी के बार्सिलोना द्वारा की गई पेशकश पर विचार करने की संभावना है, यह उम्मीद की जाती है कि यह सौदा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से उनके विवादास्पद निकास के बाद अल नस्र से प्राप्त राशि से अधिक होगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 115 अंक चढ़कर 59 हजार के पार बंद

नईदिल्ली। स्थानीय शेयर बाजार में सोमवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी का सिलसिला जारी रहा और बीएसई सेंसेक्स लगभग 115 अंक चढ़ गया। कच्चे तेल के दाम में तेजी के बावजूद मुख्य रूप से वाहन, बैंक और पूंजीगत सामान कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी आई। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 114.92 अंक यानी 0.19 प्रतिशत की तेजी के साथ 59,106.44 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 58,793.08 से 59,204.82 अंक के दायरे में रहा। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में 22 लाभ में जबकि आठ नुकसान में रहे। पचास शेयरों पर आधारित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 38.30 अंक यानी 0.22 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,398.05 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी के शेयरों में 32 लाभ में जबकि 18 नुकसान में रहे। पिछले तीन सत्रों में सेंसेक्स 1,492 अंक यानी 2.51%, जबकि निफ्टी 446 अंक यानी 2.9% मजबूत हुआ है।

आज से खुल रहा है आईपीओ

नईदिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी एवलॉन टेक्नोलॉजीज सोमवार यानी 3 अप्रैल को अपना आईपीओ लेकर आई। ऐसे में अगर आप प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन इनवेस्टमेंट के लिए अच्छा साबित हो सकता है। बता दें कि पब्लिक ऑफरिंग के लिए 415-436 रुपए प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया गया है। ये आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 6 अप्रैल तक खुला रहेगा। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 865 करोड़ रुपए जुटाने की सोच रही है। डीआरएचपी फाइलिंग में कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, एवलॉन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का प्राइस बैंड 415 रुपये प्रति शेयर से लेकर 436 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इसमें 75 फीसदी का कोटा क्यूआईबी के लिए, 15% का कोटा एनआईआई के लिए और 10% का कोटा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। यह आईपीओ पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 3 से 6 अप्रैल तक खुला रहेगा।

मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां मार्च में 3 महीने के उच्च स्तर पर

नईदिल्ली। नए ऑर्डर तथा उत्पादन में विस्तार होने और मांग में जुझारूपन तथा लागत दबाव में कमी आने के बीच देश के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां मार्च महीने के दौरान तीन महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। सोमवार को जारी मासिक सर्वेक्षण में यह कहा गया। एसएंडपी ग्लोबल भारत विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) मार्च माह में बढ़कर 56.4 पर पहुंच गया। इससे पहले फरवरी में यह 55.3 पर था, जो 2023 में अब तक परिचालन परिस्थितियों में सबसे मजबूत सुधार दर्शाता है। मार्च के पीएमआई आंकड़े के अनुसार, लगातार 21वें महीने के लिए समग्र परिचालन स्थितियों में सुधार हुआ है। पीएमआई में आंकड़ा 50 से ऊपर रहने का अर्थ है कि कारोबारी गतिविधियों में विस्तार हुआ है, जबकि 50 से नीचे रहने का मतलब इसमें गिरावट हुई है। अर्थशास्त्र की सहायक निदेशक पॉलियाना डी लीमा ने कहा, मार्च में भारतीय सामानों की अंतर्निहित मांग मजबूत रही।

भारत में लॉन्च हुआ नोकिया का सस्ता स्मार्टफोन

नईदिल्ली। अगर कम बजट वाले स्मार्टफोन को खरीदने की सोच रहे हैं तो नोकिया ने भारत में अपना नया फोन नोकिया सी12 प्लस को लॉन्च कर दिया है। नोकिया सी12 प्लस के स्पेसिफिकेशन फोन एंड्रॉयड 12 का गो एडिशन है। इसके अलावा फोन में 6.3 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले की स्टाइल वॉटरड्रॉप नॉच है। इसमें कर्व्ड फ्रेम और बॉडी है। नोकिया ने अपने नोकिया सी12 प्लस प्रोसेसर नए फोन में Unisoc का ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया है जिसकी क्लॉक स्पीड 1.6 हार्टज है। नोकिया सी12 प्लस स्टोरेज में कंपनी ने नोकिया सी12 प्लस में 2 जीबी रैम के साथ 32 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी है । नोकिया सी12 प्लस फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस रियर कैमरा मिलेगा, जिसके साथ एलईडी फ्लैश लाइट भी दी गई है । वहीं फ्रंट कैमरा यह 5 मेगापिक्सल का है।

मिशन मोड में भारत की पर्यटन क्षमताओं को बढ़ावा

पुनीत चटवाल

पूरी दुनिया में सबसे तेजी से उभरते पर्यटन गंतव्यों में से एक, भारत का यात्रा और पर्यटन क्षेत्र, भरोसेमंद विकास की रूपरेखा प्रदान करता है; एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद, अब यह क्षेत्र बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार है। पर्यटन क्षेत्र को एक मिशन के तौर पर विकसित करने के लिए, भारत के बजट 2023 में विभिन्न पहलों और योजनाओं की रूपरेखा पेश की गई है। बजट-उपरांत सत्र में, माननीय प्रधानमंत्री ने भारत के विकास को गति देने में पर्यटन क्षेत्र के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र जीडीपी और रोजगार सृजन दोनों में योगदान दे सकता है। प्रधानमंत्री का यह कथन, पर्यटन क्षेत्र में मौजूद अपार संभावनाओं का प्रमाण है। उद्योग जगत के हितधारकों और सरकार के बीच सामूहिक कार्रवाई पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि इस क्षेत्र के लिए अब तक के सबसे उज्ज्वल भविष्य का निर्माण किया जा सके और यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था तथा पूरे समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम हो सके।

केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहन देने का मूल आधार इस तथ्य की स्वीकृति है कि यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। केंद्रीय बजट ने सहयोग के लिए, छह विषयों को रेखांकित किया है, जिनमें से दो विषय हैं ङ्ग आपसी तालमेल और सार्वजनिक-निजी-भागीदारी। पर्यटन को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग के महत्व पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। विकास का एक प्रमुख कारक होने के अलावा; यह आपसी सहयोग,

रचनात्मकता को प्रोत्साहन देता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है और दूरदर्शी परिणाम प्राप्त करता है। यदि संबंधित पक्ष अलग-अलग काम करते हों, तो इन परिणामों को हासिल करना एक कठिन कार्य हो सकता है। उदाहरण के लिए, काशी विश्वनाथ धाम मंदिर में आगंतुकों की संख्या, पिछले साल के औसत 80 लाख से बढ़कर 7 करोड़ हो गयी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास नव विकसित स्थल को, अंतिम रूप दिए जाने के बाद, एक वर्ष की अवधि में 27 लाख लोगों ने देखा।

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जिन छह विषयों को रेखांकित किया गया है, उनमें पहला है- पर्यटन स्थल केंद्रित दृष्टिकोण। यह भविष्य के पर्यटन केंद्रों के रूप में 50 पर्यटन-स्थलों को प्रोत्साहन देने के लिए शासन के विभिन्न प्रभागों को एक साथ लाने की बात करता है। प्रधानमंत्री ने काशी, केदारनाथ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और पावागढ़ जैसे स्थानों का उदाहरण दिया, यह बताने के लिए कि कैसे एकीकृत दृष्टिकोण के साथ सरकार के विभिन्न विभागों के एक साथ आने से इन स्थानों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हो सकती है। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान और 'देखो अपना देश' की पहल ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया, जिससे आतिथ्य-सत्कार क्षेत्र की कंपनियों को सभी क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़ाने का अवसर मिला- व्यवसाय, विलासितापूर्ण संपत्तियों, होम स्टे, विला आदि से लेकर बजट होटलों तक। इन 50 पर्यटन-स्थलों के विकास से आने वाले वर्षों में न केवल स्थितियां बेहतर होंगी, बल्कि भारत में पर्यटन क्रांति की भी शुरुआत होगी। पर्यटन एक सामाजिक-आर्थिक गतिविधि है और विकास के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है, जो सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के साथ पर्यावरण आधारित उचित प्रबंधन को संतुलित करता है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले विषयों की सूची में एक महत्वपूर्ण विषय है- इस क्षेत्र में चल रही डिजिटलीकरण और नवाचार की प्रक्रिया। डिजिटल तकनीक, ए.आर./वी.आर. और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस); यात्रा और पर्यटन उद्योग में क्रांति लाने के लिए तैयार हैं। यात्रा-अनुभव, पहले से कहीं अधिक व्यक्ति-केन्द्रित, बहु-आयामी और आपसी संवाद आधारित होते जा रहे हैं।

सावरकर के सम्मान की रक्षा के लिए एक साथ

नीरज कुमार दुबे

महाराष्ट्र में शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस राजनीति में तीन धूरी हो लेकिन सावरकर के सम्मान में सभी एकमत हैं। राहुल गांधी लगातार सावरकर के खिलाफ बयान देते हैं, आबकि बार सभी दलों ने मिलकर सावरकर के सम्मान में खड़े नजर आ रहे हैं। छत्रपति संभाजी नगर (पुराना नाम औरंगाबाद) में साम्प्रदायिक हिंसा के कुछ दिन बाद महा विकास आघाड़ी (एमवीए) की पहली रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने 'सावरकर गौरव यात्रा' को लेकर भाजपा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि पवित्र भगवा (ध्वज) उनके हाथों में अच्छा नहीं लगता। ठाकरे ने सवाल किया, ''सावरकर ने देश की स्वतंत्रता के लिए कठोर कारावास और कठिनाइयां झेलीं, न कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। क्या आप सावरकर के 'अखंड भारत' के सपने को पूरा करेंगे?'' उल्लेखनीय है कि एमवीए में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), राकांपा और कांग्रेस शामिल हैं। ठाकरे ने कहा, ''भाजपा और (एकनाथ) शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को सावरकर तथा सरदार पटेल के आदर्शों पर चलना चाहिए। कुछ समय पहले अमित शाह ने महाराष्ट्र में भाजपा से उद्धव ठाकरे को उनकी 'जगह' दिखाने को कहा था। यह मेरी जगह है। लेकिन आप हमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में जगह कब दिखाएंगे?'' दूसरी ओर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी रविवार को अपने गृह नगर ठाणे शहर में 'सावरकर गौरव यात्रा' की अगुवाई की जिसमें हिंदुत्व विचारक दिवंगत सावरकर के सम्मान में सैंकड़ों लोगों ने भाग लिया। भाजपा और शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने पिछले महीने घोषणा की थी कि देश में सावरकर के योगदान को सम्मान देने तथा उनके खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना का जवाब देने के लिए महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में सावरकर गौरव यात्रा निकाली जाएगी।लोगों ने भगवा टोपियां पहनकर यात्रा में भाग लिया जिन पर 'मी सावरकर' (मैं सावरकर हूं) तथा अन्य संदेश लिखे थे। उन्होंने ठाणे शहर में राम गणेश गडकरी रंगायतन सभागार में सावरकर को पुष्पांजलि अर्पित की, जहां से यात्रा आरंभ हुई थी। रैली समाप्त होने पर एक सभा को संबोधित करते हुए शिंदे ने सावरकर पर बार-बार हमला करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की और कहा कि स्वतंत्रता सेनानी का अपमान देश का अपमान करने के समान है। उन्होंने कहा कि लोग सावरकर पर हमला कर हिंदुत्व की छवि बिगाड़ने की कोशिश करने के लिए कुछ ताकतों से आक्रोशित हैं। दूसरी ओर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के देश की आजादी के लिए दिए गए बलिदान की कोई अनदेखी नहीं कर सकता है, लेकिन उनसे असहमति को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि आज देश के समक्ष कई और ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। नागपुर के प्रेस क्लब में शरद पवार ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। वह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर स्थित आवास पर उनसे मिलने भी गए। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी से बात की है और क्या कांग्रेस नेता दिवंगत हिंदुत्व विचारक की आलोचना में कमी लाएंगे तो पवार ने कहा कि हाल में 18-20 पार्टियां एक साथ बैठीं और देश के समक्ष मौजूद मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, ''मैं सुझाव दूंगा कि इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि जो इस समय सत्ता में हैं वे देश को किस ओर ले जा रहे हैं।'' पवार ने कहा, ''आज, सावरकर राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, यह पुरानी चीज हो गई है। हमने सावरकर के बारे में कुछ बातें कही हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत नहीं हैं। मैं हिंदू महासभा के खिलाफ था, लेकिन दूसरा पक्ष भी है। हम सावरकर द्वारा देश की आजादी के लिए दिए गए बलिदान की अनदेखी नहीं कर सकते हैं।''

कौन अयोग्य हो सकता है, किसकी मानहानि हुई?

पी. चिदंबरम

अदालतों की स्थापना कानून के मुताबिक न्याय देने के लिए की जाती हैं। कई बार, न्याय लड़खड़ा जाता है, लेकिन भारत में वादी यथोचित उम्मीद कर सकते हैं कि यदि वे टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर यात्रा जारी रखेंगे, तो अंतत: उन्हें न्याय मिल ही जाएगा। इस भूमिका के साथ मैं एक ऐसे मामले की व्याख्या करूंगा, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है और जिसने राजनीतिक विभाजन के दोनों ओर भावनाओं को उत्तेजित किया है। 23 मार्च, 2023 को गुजरात के एक मजिस्ट्रेट ने श्री राहुल गांधी को मानहानि (आईपीसी की धारा 499) के अपराध में दोषी ठहराया और उन्हें दो वर्ष के कैद की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद मजिस्ट्रेट ने सजा पर रोक लगा दी। इसके बावजूद, 24 मार्च को श्री गांधी को अयोग्य घोषित कर लोकसभा की उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया।

मामला इस तरह बढ़ा

13.04.2019ः श्री गांधी ने कोलार, कर्नाटक में एक भाषण दिया। 16.04.2019ः श्री पूर्णेश मोदी, विधायक (भाजपा) ने सूरत, गुजरात में मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की कि श्री गांधी ने पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। 07.03.2022 शिकायतकर्ता के आग्रह पर उनकी अपनी शिकायत की सुनवाई पर गुजरात उच्च न्यायालय ने स्थगन दे दिया। 07.02.2023 श्री गांधी ने लोकसभा में अदाणी समूह के मुद्दों पर भाषण दिया। 16.02.2023ः शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापस ले ली। 21.02.2023ः मजिस्ट्रेट ने सुनवाई बहाल कर दी। 17.03.2023 सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। 23.03.2023ः मजिस्ट्रेट ने 168 पेज का फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने श्री गांधी को दोषी करार दिया और उन्हें दो साल की सजा सुनाई, थोड़ी देर बाद मजिस्ट्रेट ने सजा पर रोक भी लगा दी। 24.03.2023 लोकसभा सचिवालय ने श्री गांधी की अयोग्यता को लेकर अधिसूचना जारी कर दी।

तीन बरस से अपनी गति से चल रहा यह नियमित मामला अचानक महत्त्वपूर्ण हो गया और प्रकाश की गति से 30 दिनों में इसमें सुनवाई बहाल होने से लेकर सजा तक हो गई। पहेली यह है कि किस वजह से यह इतना महत्वपूर्ण हो गया? शिकायतकर्ता ने अपनी ही शिकायत पर स्थगन क्यों लिया था और फिर लोकसभा में श्री गांधी के भाषण के नौ दिनों के बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस लेकर स्थगित सुनवाई को तुरंत बहाल करने का आग्रह क्यों किया?

किसकी मानहानि हुई?

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मोदी समुदाय/जाति, जिससे वह खुद ताल्लुक रखते हैं, की मानहानि हुई। साफ कहूं, तो मैं नहीं जानता कि ऐसा कोई समुदाय है, जिसे मोदी कहा जाता है या जिन लोगों के उपनाम मोदी हैं, वे सब एक समुदाय या जाति के हैं। द इंडियन एक्सप्रेस (28 मार्च, 2023) ने विस्तार से बताया था कि मोदी शब्द किसी एक विशेष समुदाय या जाति से संबंधित नहीं है। गुजरात में मोदी उपनाम का उपयोग हिंदू, मुस्लिम और पारसी करते हैं। वैष्णव (बनिया), पोरबंदर के खारवा (मछुआरे) और लोहाना (व्यवसायी समुदाय) में मोदी उपनाम लगाने वाले लोग हैं। अखबार ने यह भी पाया कि ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) की सूची में मोदी नाम का कोई समुदाय या जाति नहीं है। इसके अलावा बिहार और राजस्थान के लिए केंद्रीय सूची में भी कोई मोदी नहीं है। गुजरात की केंद्रीय सूची में मोदी घांची है।

मैंने छह दशक पहले जाति को त्याग दिया था और मैं जाति को मान्यता नहीं देता। एक समुदाय/जाति (कथित रूप से 13 करोड़ मजबूत) को बदनाम करने के तर्क से मेरा सिर घूम गया है।

शिकायत के मुताबिक यह मानहानि का मामला था। आईपीसी की धारा 500 के तहत सजा दो साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। मैं मानहानि के ऐसे एक भी मामले के बारे में नहीं जानता, जिसमें 1860 (जब से आईपीसी अस्तित्व में आया) के बाद से किसी को अधिकतम दो साल की सजा दी गई हो। अमूमन जब तीन साल या उससे कम की कैद की सजा सुनाई जाती है, तब आरोपी को जमानत मिल जाती है और वह आजाद व्यक्ति होता है, ताकि वह दोषसिद्धि और सजा से राहत के लिए उच्चतर अदालत जा सके। हालांकि इस मामले में खुद मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाने के कुछ मिनटों बाद ही उस पर रोक लगा दी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का अनुच्छेद 8 (3) कहता हैः %कोई भी व्यक्ति जिसे वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो वह दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य हो जाएगा...राहुल गांधी के मामले में दोषसिद्धि तो हुई, लेकिन सजा प्रभावी नहीं हुई। इसलिए क्या वह 23 मार्च, 2023 को अयोग्य हो सकते थे? यह बहस का मुद्दा है। अनेक लोगों ने यह सवाल पूछा है और उन्हें जवाब का इंतजार है। हालांकि जिनके पास भी शक्तियां थीं, उन्हें संदेह नहीं था। पता नहीं, यह सवाल पूछा भी गया या नहीं और इसका जवाब मिला या नहीं, लेकिन 24 घंटे के भीतर लोकसभा सचिवालय ने श्री गांधी को अयोग्य कर दिया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (2) (ई) के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति... सदस्य होने के अयोग्य हो जाएगा... यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य हो जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यहां स्वत: अयोग्य हो जाएगा, नहीं बल्कि, अयोग्य हो जाएगा, प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि अयोग्यता का आदेश आवश्यक होगा। स्वाभाविक प्रश्न पूछा गया (प्रश्न पूछने वालों में श्री पीडीटी आचार्य, लोकसभा के पूर्व महासचिव शामिल हैं) कि अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसके पास है? अनुच्छेद 103 में इसका उत्तर मिल सकता हैः इसके मुताबिक, यदि कोई प्रश्न उठता है.... प्रश्न राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेजा जाएगा, जो कि चुनाव आयोग की राय लेंगे और उस राय के अनुसार कार्य करेंगे। श्री गांधी के मामले में प्रश्न राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा गया; न ही चुनाव आयोग ने कोई राय दी। तो फिर फैसला किसने लिया? क्या माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने लिया या उस संस्था ने लिया, जिसे लोकसभा सचिवालय के रूप में जाना जाता है? यह कोई नहीं जानता। चर्चिल की तर्ज पर कहें, तो यह मामला और उसके परिणाम रहस्य में लिपटी किसी पहेली की तरह हैं।

प्रसंग — अहिंसा परमो धर्म

भगवान् महावीर का उपदेश सुनने एक दिन मगधसम्राट् श्रेणिक स्वयं जा पहुँचा। भगवान् ने उस दिन प्रवचन में नरक के दारुण कष्टों का वर्णन किया और नरकवास टालने का उपाय बताया। साथ ही यह भी कहा कि अपने किये कर्मों को स्वयं को ही झेलना पड़ता है।

राजा तब वापस लौटने लगा, तो उसे रास्ते में कसाईघर दिखाई दिया। कालसौकरिक नामक एक कसाई वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों भैंसों का वध करता। राजा ने उससे हिंसा त्यागने का आग्रह किया, बदले में मुँहमाँगा धन देने का प्रलोभन दिया। कालसौकरिक ने स्पष्ट रूप से कहा, राजन्! आपका धन मिलने से मेरी वृत्ति में कोई अन्तर न पड़ेगा। मैं अपनी कमाई खाता हूँ और जीव-हिंसा ही मेरी कमाई है उसकी यह स्पष्टोक्ति सुन राजा को गुस्सा आया और उसने कसाई को अन्धकूप में डालने का अपने सैनिकों को आदेश दिया।

अगले दिन श्रेणिक भगवान् महावीर के पास जा पहुँचा और उसने कसाई को दण्ड देने की बात बताकर कहा, भगवन्! मैंने उसे कठोर दण्ड दिया है, अब वह भैंसों को मार नहीं सकेगा। सुनकर भगवान् मुसकराये, बोले, राजन्! यह आपका भ्रम है ! वह कसाई हिंसा-कर्म करने का इतना आदी हो चुका है कि उससे यह दुष्कर्म कभी भी छूट नहीं सकता। राजा तुरन्त अन्धकूप जा पहुँचा, मगर वह यह देख हैरान रह गया कि कसाई ने वहाँ मिट्टी के सैकड़ों भैंसे बनाकर उन्हें तोड़ दिया है। वह समझ गया कि हिंसा हृदय-परिवर्तन से छूट सकती है, जोर-जबरदस्ती से नहीं। और उसने कालसौकरिक को मुक्त कर दिया।

कालसौकरिक की मृत्यु के बाद जब उसके लड़के सुलस को अपने पिता का पेशा अपनाने का उसके बिरादरीवालों ने आग्रह किया, तो उसे साफ-साफ बताया कि वह पाप का यह पेशा कभी नहीं अपनाएगा। उसे उसकी माता ने महावीर के उपदेश की बात बतायी थी और इसका उस पर प्रभाव पड़ा था। लेकिन लोग न माने और उस पर जबरदस्ती करने लगे। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, वे उसके साथ हैं। सुलस ने तुरन्त कुठार उठाया और सामने खड़े भैंसे की ओर देखा। लोग यह देख खुश हो गये, मगर उसने भैंसे पर वार न कर अपनी जाँघ पर वार किया। इससे वहाँ से रक्त की धार बह चली। लोग यह देख घबरा गये और महलहम पट्टी करने लगे। तब सुलस बोला, मलहम पट्टी से कुछ न होगा। कृपया मेरी पीड़ा को बटाएँ। बहुत पीड़ा हो रही है। लेकिन सब खामोश रहे। तब वह बोला, जब तुम मेरी पीड़ा में हाथ बटा नहीं सकते, तो मेरे पापों के भागीदार कैसे बनोगे? मैं हिंसा कभी भी नहीं कर सकता, फिर चाहे वह पैतृकी ही क्यों न हो। यह कोई जरूरी नहीं कि अगर पिता अन्धा हो तो पुत्र को भी अन्धा ही होना चाहिए।

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

1960 सेनेगल ने फ्रांस के साथ बिजली समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो देश की आजादी के लिए अग्रणी था।
1968 अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग, जूनियर की मेम्फिस, टेनेसी में हत्या कर दी गई थी।
1969 सर्जन डेंटन कोलेई और डोमिंगो लिओटा ने पहले कुल कृत्रिम हृदय को प्रत्यारोपित किया।
1973 न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आधिकारिक तौर पर समर्पित किया गया था, भवन परिसर के जुड़वाँ के दूसरे पूरा होने के लगभग एक साल बाद।
1975 न्यू मैक्सिको में बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट को अल्बुकर्क में स्थापित किया।
1976 नॉरडोम सिहानौक को कंबोडिया के नेता की भूमिका से अलग किया गया और उसे खमेर रूज ने गिरफ्तार कर लिया।
1977 न्यू होप, जॉर्जिया में एक राजमार्ग पर दक्षिणी एयरवेज की उड़ान 242 दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 72 लोग मारे गए।
1979 अपदस्थ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को मार दिया गया।
1984 अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने रासायनिक हथियारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध के लिए कहा।
1988 एरिज़ोना के गवर्नर इवान मेखम को महाभियोग के मुकदमे में दोषी ठहराए जाने के बाद पद से हटा दिया गया था।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

योगतत्त्वापनिषद् (भाग-04)

गतांक से आगे...

ऐसे योगी की पृथ्वी के संयोग (विकार या आघात) से मृत्यु नहीं होती। घुटनों से गुदास्थान तक जल तत्त्व का क्षेत्र बतलाया गया है। यह जल तत्त्व अर्द्ध चन्द्र के रूप में वं बीज वाला होता है। इस जल तत्त्व में वायु को आरोपित करते हुए वं बीज को समन्वित करके चतुर्भुज, मुकुट धारण किये हुए, पवित्र स्फटिक के सदृश, पीत वस्त्रों से आच्छादित अच्युतदेव श्री नारायण का पाँच घटी (2 घंटे) तक ध्यान करना चाहिए। इससे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है।

इसके पश्चात् उस योगी को जल से किसी भी तरह का डर नहीं रहता और न ही जल से उसकी मृत्यु हो सकती है। जलतत्त्व (गुदा भाग) से हृदय क्षेत्र तक अग्नि का स्थान बताया गया है। तीन कोणों से युक्त अग्नि, लाल रंग वाला एवं र कार से संयुक्त होता है। अग्नि में वायु को आरोपित करके उस समुज्ज्वल र कार को समन्वित करना चाहिए। त्रियक्ष (तीन नेत्रों) से युक्त वर प्रदान करने वाले, तरुण आदित्य के सदृश प्रकाशमान तथा समस्त अङ्गों में भस्म धारण किये हुए भगवान् रुद्र का प्रसन्न मन से सदा ध्यान करना चाहिए।

पाँच घटी (2 घंटे) तक इस तरह से चिन्तन करने से वह (योगी) अग्नि से नहीं जलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रखर जलती हुई अग्नि में भी संयोगवश प्रविष्ट कराया जाए, तो भी वह नहीं जलता। हृदय क्षेत्र से भृकुटियों तक का स्थान वायु का क्षेत्र कहा गया है, यह षट्कोण के आकार वाला, कृष्ण वर्ण से युक्त भास्वर य अक्षर वाला होता है। मस्तु स्थान पर यकार होता है। यहाँ य अक्षर के सहित विश्वतोमुख सर्वज्ञ ईश्वर का सतत चिन्तन कर। इस तरह पाँच घटी अर्थात् दो घंटे तक उन विश्वतोमुख भगवान् का ध्यान करने से योगी वायु के सदृश आकाश में गमन करने वाला हो जाता है। उस महान् योगी को वायु से किसी भी तरह का भय नहीं व्याप्त होता तथा वह वायु से मृत्यु को भी नहीं प्राप्त होता।

भृकुटी के मध्य भाग से लेकर मूर्धा के अन्त तक का आकाश तत्त्व का क्षेत्र कहा गया है। यह व्योमवृत्त के आकार वाला, धूम्र वर्ण से युक्त तथा ह कार (अक्षर) से प्रकाशित है। इस आकाश तत्त्व में वायु का आरोपण करके ह कार के ऊपर भगवान् शंकर (का ध्यान करे), जो बिन्दु रूप महादेव हैं। वही व्योमाकार में सदाशिव रूप हैं। वे भगवान् शिव परम पवित्र स्फटिक के सदृश निर्मल हैं, बालरूप चन्द्रमा को मस्तक में धारण किये हुए हैं, पाँच मुखों से युक्त, सौम्य, दश भुजा एवं तीन नेत्रों से युक्त हैं। वे भगवान् शिव सभी प्रकार के शस्त्रास्त्रों को धारण किये हुए, विभिन्न प्रकार के आभूषणों से विभूषित, पार्वती जी से सुशोभित अर्धाङ्ग वाले, वर प्रदान करने वाले तथा सभी कारणों के भी कारण रूप हैं।

क्रमशः...

अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस

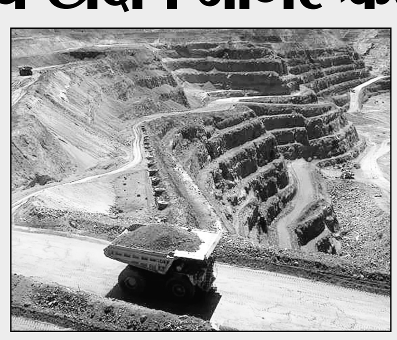

संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है। 8 दिसंबर 2005 को, महासभा ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था।

इस वर्ष, संयुक्त राष्ट्र ने इस चुनौतीपूर्ण वर्ष के माध्यम से दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति को उजागर करके खान कार्रवाई को बढ़ावा दिया। दिन का लक्ष्य बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके उन्मूलन की दिशा में प्रगति करना है। माइन एक्शन में बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों को हटाने और खतरनाक क्षेत्रों को चिह्नित करने और बाड़ लगाने के प्रयासों की एक श्रृंखला है। इसमें पीड़ितों की सहायता करना, लोगों को खदान-प्रभावित माहौल में सुरक्षित रहना सिखाना, खदानों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियों में सार्वभौमिक भागीदारी, युद्ध और उनके पीड़ितों के विस्फोटक अवशेषों की वकालत करना, तथा सरकारों और गैर-राज्य सशस्त्र समूहों द्वारा भंडारित किए गए बारूदी सुरंगों को नष्ट करना शामिल है।

ज़मीन या पहाड़ पर खनिज पदार्थों की खोज में खुदाई करके बनाया गया गड्ढा 'खदान' कहलाता है, आमतौर पर इसे खान भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाए जाने की घोषणा यूएन जनरल असेंबली द्वारा 8 दिसंबर 2005 को की गयी थी, जिसमें 4 अप्रैल को हर वर्ष 'इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन' मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। महासभा द्वारा इस दिन को रेखांकित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि सभी देशों में राष्ट्रीय खदान-कार्य क्षमता को स्थापित किया जा सके। जिसके बाद 4 अप्रैल, 2006 को इसे पहली बार मनाया गया था।

पिछले 20 सालों से प्रभावित लोगों की जरूरतों, समस्याओं और आम नागरिकों के खतरों का समाधान संयुक्त राष्ट्र माइन एक्शन सर्विस द्वारा किया जा है। यह नागरिकों की रक्षा करने के साथ ही मानव अधिकार कानून आदि की रक्षा भी करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र माइन एक्शन सर्विस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2023 की थीम माइन एक्शन कैन नॉट वेट रखी है। तो वहीं पिछली साल 2022 में माइन अवेयरनेस डे को सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर विषय के साथ मनाया गया था।

कर्नाटक में पूरी हुई पसमांदा मुसलमानों की पुरानी मांग

फयाद अहमद फैजी

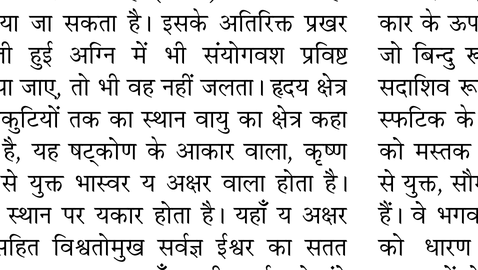

पिछले दिनों कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की अनुशंसा पर ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत केवल मुस्लिमों के लिए आवंटित कैटेगरी 2बी (4%) को समाप्त कर इसमें आने वाले मुस्लिमो को ईडब्ल्यूएस (10%) में शिफ्ट कर दिया। और 2बीके 4% को दो बराबर भागों में विभाजित कर ओबीसी की अन्य कैटेगरी 3 ए (अब 2सी) और 3बी (अब 2डी) को दे दिया। इस खबर को लेकर अधिकतर मीडिया (अंग्रेजी-हिन्दी) ने यह हेडिंग बनाई कि मुस्लिम आरक्षण समाप्त हो गया है जिससे समाज में यह गलत सूचना गई कि सारे मुस्लिमों का आरक्षण समाप्त हो गया है। जबकि सामाजिक न्याय के आरक्षण के लिए योग्य मुस्लिमों की अधिकतर पसमांदा जातियों को ओबीसी की कैटिगरी 1 (4%), 2 (15%) और एसटी (7%) में रखा गया है, जो यथावत बरकरार भी है। यानी पसमांदा जातियों को पहले की तरह ओबीसी के 19% और एसटी के 7% आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। सरकार ने सिर्फ 4% वाले 2बी को समाप्त किया है जिसका लाभ अब तक सशक्त शासक वर्गीय अशराफ मुसलमान उठा रहे थे। यह संविधान और सामाजिक न्याय संगत नहीं था।

मजहबी पहचान के नाम पर आरक्षण संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। कोई भी मजहब पिछड़ा दलित नहीं है। उसके मानने वालो में पिछड़ा दलित हैं जिन्हें आरक्षण में समाहित किया गया है। (एससी आरक्षण को छोड़ कर इसमें ईसाई और मुस्लिम धर्म के दलित अभी भी बाहर हैं) मुस्लिम विमर्श की राजनीति करने वाली मुस्लिम सांप्रदायिक राजनैतिक पार्टी एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी और मुस्लिम मजहबी सांप्रदायिक संगठन जमीयतुल उलेमा ने इसे सांप्रदायिक मुद्दा बना माहौल गरमाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। जमीयतुल उलेमा ने विधिवत प्रेस रिलीज जारी कर यह भ्रम फैलाते हुए कि 2बी में मुसलमानों की 12 पिछड़ी जातियां भी हैं, इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की बात तक कह दी।

ज्ञात रहे कि कर्नाटक ओबीसी आरक्षण की जातियों की लिस्ट में अन्य कैटेगरी में तो जातियों के नाम दर्ज हैं लेकिन 2बी में सिर्फ मुस्लिम लिखा हुआ है किसी जाति विशेष या जातियों के नाम एवं संख्या वर्णित नहीं हैं। यह भी एक विडम्बना है कि 2क्ष कैटिगरी के लिए बनने वाले कास्ट सार्टिफिकेट में कास्ट का नाम मुस्लिम लिखा रहता है जो कि ठीक नहीं है क्योंकि मुस्लिम एक धार्मिक पहचान है ना कि जातीय पहचान। ऐसा प्रतीत होता है कि शासक वर्गीय अशराफ ने पूर्ववर्ती सरकारों और बुद्धिजीवियों को गुमराह कर अपना स्वार्थ साधने के लिए ओबीसी आरक्षण में यह चोर दरवाजा खुलवाया था। मुख्यधारा की इंग्लिश हिंदी मीडिया और ओवैसी, मदनी के इस रवैये से देशज पसमांदा समाज में भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई कि कर्नाटक सरकार ने वंचित पसमांदा का भी आरक्षण खत्म कर दिया है। जहां तक पसमांदा जातियों के आरक्षण की बात है तो अधिकतर पसमांदा जातियां जैसे नट, नेटुआ, जोगी, कंजड़, भांट, कसाई, कलाल, मदारी, सिकलगर, बेलदार, छप्परबंद, नीरशिकार, मंसूरी, दुदेकला, नद्दाफ आदि पहले की तरह ओबीसी की कैटेगरी 1 में हैं। धोबी, हज्जाम, दर्जी, लोहार, गद्दी, रंगरेज, जुलोही(बुनकर), तेली आदि कैटेगरी 2ए में हैं। तथा सिद्दी, तड़वी भील, टोडा आदि जनजाति को एसटी में यथावत रहने दिया गया है। यदि केवल मुस्लिम आरक्षण की कैटेगरी 2बी में आने वाली मुस्लिमों की जातियों की सूची होती तो स्थिति स्पष्ट हो जाती। यदि हम यह मान भी लें कि 2बी में कुछ पसमांदा जातियां भी थी तो फिर भी यह अनुचित था क्योंकि कमज़ोर पिछड़ी जातियां मजबूत शासक वर्गीय अशराफ जातियों से एक ही कैटेगरी में मुकाबला नहीं कर सकती थीं। इससे आरक्षण योजना का उद्देश्य बाधित हो रहा था।

विदित होता है कि ओबीसी के कैटेगरी 2बीआरक्षण का सारा लाभ मुसलमान नाम पर सैयद, पठान लोग (अशराफ) ही उठा रहे थे जो कि आरक्षण की मूल भावना के विपरीत था। ऐसे में यह उचित प्रतीत होता है कि सरकार, बैकवर्ड कमीशन और सामाजिक कार्यकर्ता ओबीसी आरक्षण में शामिल होने से छूट चुकी उन पसमांदा जातियों की पहचान कर उनको ओबीसी आरक्षण की उपयुक्त श्रेणियों में समाहित करने का प्रयास करें। पसमांदा आंदोलन का यह स्पष्ट मानना रहा है कि देशज पसमांदा समाज का उत्थान उसकी सामाजिक शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो ना कि उसकी मजहबी पहचान मुस्लिम के आधार पर। इसीलिए पसमांदा आंदोलन की यह बहुत पुरानी मांग रही है कि अनुच्छेद 341 के पैरा 3 को हटाकर पसमांदा दलितों को भी एससी आरक्षण में सम्मिलित किया जाय। दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों यथा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के ओबीसी आरक्षण से शासक वर्गीय सशक्त अशराफ जातियों को बाहर निकाला जाय ताकि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय में अवरोध न उत्पन्न हो और मुस्लिमों की योग्य जातियों को ही इसका लाभ मिल सके। कर्नाटक सरकार की मंशा चाहे जो रही हो, पसमांदा आंदोलन की यह एक पुरानी मांग पूरी हुई जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। कर्नाटक की तरह ही केरल और तमिलनाडु में भी ओबीसी आरक्षण से सशक्त शासक वर्गीय अशराफ जातियों को बाहर कर ओबीसी आरक्षण का बिहार मॉडल अपनाना अधिक उचित होगा। ताकि वंचित देशज पसमांदा मुसलमानों को पूर्णत: सामाजिक न्याय मिल सके और शासक वर्गीय विदेशी अशराफ द्वारा आरक्षण का अनुचित लाभ लेना बंद हो सके।

गांधी आज

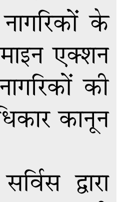

स्वावलंबी और व्यापारी खादी (भाग-02)

बल्कि उन्हें प्रत्येक मजदूर के जीवन में प्रवेश करना और यह देखना चाहिए कि वह अपने धंधे में अच्छे से अच्छा कारीगर हो अपनी आमदनी अच्छे से अच्छे तरीके से खर्च करे। खादी के विषय में नीचे बताए नियम तमाम ग्राम उद्योगों पर यथायोग्य रीति से लागू किए जा सकते हैं-प्रत्येक कार्यकर्ता को कपास चुनने से लेकर सूत बनने तक की सभी क्रियाएं ठीक तौर से जान लेनी चाहिए, जिससे वह दूसरे को भी सिखा सके। व्यवस्थापकों को अपने-अपने क्षेत्र में काम करनेवाले धुनियाँ, कतैयों और बुनैयों की एक फेहरिस्त रखनी चाहिए। अपने कातनेवाले कौन सी रूई इस्तेमाल करते हैं यह भी वे जान लें और यह ध्यान रखें कि जितने अंक तक का सूत निकालने की ताकत रूई में हो उससे अधिक नंबर का सूत न काता जाय। कत्तिनों तथा खादी बनाने में सहायक दूसरे कारीगरों से साफ कह देना चाहिए कि वे अपने घर में खादी व्यवहार न करेंगे तो उन्हें काम न मिलेगा। इस चेतावनी के साथ-साथ ऐसी सुविधा भी कर देनी चाहिए जिसमें उन्हें मजदूरी के बदले में ही खादी मिल जाय । खादी कार्यालय में आनेवाली सूत की हर एक अट्टी की मजबूती और समानता जाँचनी चाहिए और जैसे कच्ची रोटी नहीं खाई जाती वैसे ही कमजोर या असमान सूत नहीं लेना चाहिए। साधारणत: हरएक कत्तिन का सूत अलग ही रखना चाहिए। और जब कपड़ा बनाने भर को पूरा जमा हो जाय तब उसे अलग बनवा लेना चाहिए। इससे खादी मजबूत बनेगी और बुनाई तथा सफाई में भी सुधार हुए बिना न रहेगा। (ज) इस तरह तैयार हुए हरएक थान पर, यदि ओटनेवाला, धुननेवाला कत्तिन और बुनकर अलग-अलग हों तो, सबके नाम की चिट लगी होनी चाहिए। जहाँ कारीगर कुटुंबीजन हों वहाँ उपर्युक्त तमाम क्रियाएं अपने ही कुटुंब में कर लेने की प्रेरणा उन्हें करनी चाहिए और उत्तेजन देना चाहिए। **क्रमशः...**

संक्षिप्त समाचार

सड़क हादसों में तीन की मौत

रायगढ़। जिले में रविवार रात अलग-अलग दुर्घटनाओं में तीन लोगों की जान चली गई। पहली घटना कोड़ातराई के पास हुई। जहां ड्यूटी से वापस लौट रहे आरक्षक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे आरक्षक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दूसरी घटना, ग्राम डूमरमूडा की है। जहां ठेले के पास दो युवक नाश्ता कर रहे थे। इसी दौरान एक नियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे नाश्ता कर रहे दोनों युवक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल हुए दोनों युवकों ने मौके पर दम तोड़ दिया। डूमरमूडा के पास सड़क किनारे चाऊमीन ठेले में नाश्ता कर रहे दो लोगों को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। डूमरमूडा के ग्रामीण घटना के बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार ग्रामीण थाना जूट मिल का घेराव करने की योजना बना रहे हैं। मृतकों के परिजन, मुआवजे के लिए मांग कर रहे हैं। शहर में जब भी कोई हादसा होता है तो पुलिस कुछ दिनों के लिए सक्रिय हो जाती है। यातायात विभाग चौक चौराहों पर अलर्ट हो जाता है। वहीं, बेकाबू वाहन चला रहे लोगों पर कार्रवाई होती है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस इन मौतों की सुध कब लेगी यह देखना होगा। बीती रात शहर से कुछ किलोमीटर दूर दो सड़क दुर्घटनाओं से आम लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है।

महिलाओं से करोड़ों की ठगी के आरोप में कुमार सानू गिरफ्तार

दुर्ग। महिलाओं से मोती माला बनाने के नाम पर करोड़ों का ठगी करने वाले दो आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मास्टर माइंड सानू कुमार उर्फ कुमार सानू को उत्तरप्रदेश के वाराणसी से पकड़ा है। दूसरा आरोपी बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार हुआ है। महिलाओं से ठगी करने के बाद दोनों आरोपी फरार थे। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दुर्ग पहुंचने के बाद बाद पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी। आरोपी कुमार सानू दुर्ग के इंदिरा मार्केट स्थित फ्रेम कमल कॉम्प्लेक्स में होमग्रोन कॉर्पोरेशन के नाम से ऑफिस चलाता था। आरोपी ने नवंबर 2022 में मोती की माला बनवाने का काम महिलाओं को देना शुरू किया। सभी महिलाओं से ढाई हजार रुपये जमा करवाए। इस तरह उसने लगभग 9 हजार महिलाओं से 3 करोड़ रुपये जमा कराए। मोती माला पिरोने के लिए हर महिला को 3 किलो मोती देता था। जिसकी मजदूरी के रूप में 3500 रुपये प्रति महिलाओं को दिए जाते थे। कुछ दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा। इस तरह लगभग 9 हजार से ज्यादा महिलाएं आरोपी के झांसे में आ गई।

नशे के खिलाफछत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ड्रग्स और नार्कोटिक्स, अवैध नशा के खिलाफ निजात अभियान के तहत पुलिस की ताबतोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अभियान के तहत दो माह में कुल 1303 लोगों को एनडीपीएस एक्ट के गिरफ्तार किया, जिनमें से गैर जमानतीय प्रकरणों 215, 126 आबकारी, 89 एनडीपीएस के मामले से जुड़े है। 228 आरोपियों को अन्य प्रतिबंधित प्रकरणों में जेल भेजा गया है। इस वर्ष फरवरी माह से बिलासपुर संभाग आईजी बीएन मीणा, स्क्क संतोष कुमार सिंह की उपस्थिति में अवैध नशा के खिलाफअभियान निजात की शुरुआत की गई थी। सभी थाना अंतर्गत अवैध नशा के कार्य में संलिप्त लोगों के विरुद्ध ताबड़तोड़ तरीके से कार्यवाही की गई है। फरवरी माह से शुरू किए गए अवैध नशे के खिलाफ कार्यवाही और जागरूकता अभियान निजात के तहत सिर्फ दो माह में ही ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए कुल 1303 लोग गिरफ्तार किए गए है, जिनमें से गैर-जमानतीय प्रकरणों और नशे से जुड़े किए गए प्रतिबंधात्मक प्रकरणों में कुल 228 आरोपी जेल भेजे गए है। आबकारी के कुल 1212 दर्ज प्रकरणों में 2413 लीटर शराब जप्त हुई है। आबकारी में गिरफ्तार लोगों में बड़ी संख्या सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन कर हुडदंग करने वाले लोग हैं। एनडीपीएस प्रकरणों के 73 प्रकरणों में 280 किलो गांजा और अन्य नशीली वस्तुएं जप्त कर 89 आरोपियों को जेल भेजा गया है।

भालू के हमले से एक व्यक्ति की मौत

बिलाईगढ। छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ में भालू के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। क्षत-विक्षत अवस्था में व्यक्ति की लाश जंगल में पड़ी मिली। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, खुरसुला जंगल में भालू ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक का नाम पवन गोड बताया जा रहा है। फिलहाल वन विभाग की टीम मशाल के सहारे लाश को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है।

हाइवा की चपेट में आयी दो शिक्षिकाएं

बालोद। जिले से हादसे की दुःखद खबर सामने आ रही है, यहाँ ग्राम भरदा में दर्दनाक सड़क हादसे में एक शिक्षिका की मौत हो गई तो वहीं दूसरी शिक्षिका गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुर विकासखंड के गाँव चंदनबिरही स्कूल में पदस्थ दोनों शिक्षिका बोर्ड पेपर जांचने बालोद आ रही थी, इसी दरमियान गुरुर थाना क्षेत्र बालोद-गुरुर राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम भरदा के पास हाईवा ट्रक की शिकार हो गई। इस घटना मे शिक्षिका नीता बघेल ने मौके पर दम तोड़ दिया, वहीं शिक्षिका मीनू साहू गंभीर रूप से घायल है, जिन्हे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद गुरुर पुलिस मौके पर पहुंच पूरे मामले की जांच कार्रवाई में जुट गई है।

बिलासपुर विस सीट कैसे बनी हाई प्रोफाइल सीट

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं. बात अगर, बिलासपुर विधानसभा सीट की करें तो यहां वर्तमान में कांग्रेस के शैलेश पांडेय विधायक हैं. भाजपा से 15 साल मंत्री रहे अमर अग्रवाल इस सीट पर फिर अपनी दावेदारी कर सकते हैं. लेकिन अमर अग्रवाल को टिकट मिलेगा या नहीं ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है. क्योंकि यदि प्रदेश में गुजरात फॉर्मूले के तर्ज पर टिकट बांटे गए तो कई दिग्गजों का पत्ता साफ हो सकता है.

टिकट दावेदारी पर खींचतान- बिलासपुर विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी में अभी से खींचातान शुरू हो गई है. आधा दर्जन उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी को लेकर दावा ठोक रहे हैं. बिलासपुर विधानसभा के पूर्व विधायक अमर अग्रवाल लगातार चार बार विधायक रहे हैं. इस बार वो अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं. लेकिन भाजपा प्रदेश प्रभारी ने हारे हुए और निष्क्रिय विधायकों को टिकट न देने के संकेत दिए हैं. इसकी वजह से, ऐसे नेता अपनी सीट बचाने के लिए अपने-अपने स्तर पर दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं.

आखिर क्यों हॉट सीट है बिलासपुर विधानसभा सीट- बिलासपुर विधानसभा सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीट से जीतने वाले विधायकों को मंत्री पद से नवाजा जाता रहा है. जब छत्तीसगढ़ का बंटवारा नहीं हुआ तो यहां से बीजेपी के मूलचंद खंडेलवाल ने जीत दर्ज की थी. उस समय उन्हें मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री पद मिला था. इसके बाद 2003 से लेकर साल 2018 तक यहां से विधायक रहे अमर अग्रवाल लगातार मंत्री बनते रहे.

कई नेता हुए सक्रिय- बिलासपुर विधानसभा सीट के लिए नए, पुराने नेता अपनी अपनी उम्मीदवारी के लिए प्रयासरत हैं. चार साल तक नजर नहीं आने वाले नेताओं को आम जनता की समस्याएं नजर आने लगी है. वे जनता के बीच पहुंचकर, उनकी समस्याओं को जानने और समस्याओं के निपटारे का प्रयास शुरू कर चुके हैं. ऐसे में ये कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले सभी नेता अलर्ट मोड पर हैं. हालांकि इस हॉट सीट का ताज किसे मिलेगा? ये तो जनता ही तय करेगी. लेकिन सभी पार्टी के नेता सक्रिय हो गए है।

धर्मांतरित परिवार के बेटी की शादी गांव में न होने देने का आरोप

कलेक्टर से लगाई सुरक्षा की गुहार

कांकेर। कोयलीबेड़ा में धर्मांतरण कर चुके एक परिवार की लड़की की शादी गांव में होने से रोकने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार, सोमवार को कांकेर कलेक्टर प्रियंका शुक्ला के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। परिवार ने कुछ लोगों पर गांव में शादी करने पर दूल्हे तक को गायब करने का आरोप लगाया है। डरा सहमा परिवार सुरक्षा को लेकर चिंता में है और कलेक्टर से गुहार लगाई है।

12 अप्रैल को है बेटी की शादी

पीड़ित परिवार की महिला ने बताया कि वह थाना कोयलीबेड़ा क्षेत्र की निवासी है। अपने व्यक्तिगत कारणों से मसीही धर्म में सपरिवार प्रार्थना करने जाती हूं। यह मेरी व्यक्तिगत आस्था है। 12 अप्रैल को मेरी बेटी की शादी है, जिसकी जानकारी गांव के ग्रामीणों को भी है। लेकिन गांव के कुछ लोगों की ओर से बैठक कर शादी समारोह गांव में नहीं करने की बात कही जा रही है। परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। ऐसे में कलेक्टर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवेदन दी हूं ताकि शादी में कोई दिक्कत न आए और मेरी बेटी की शादी हो सके।

दूल्हे को गायब करने की दी जा रही धमकी

पीड़ित परिवार की बेटी ने बताया कि गांव के कुछ लोग धमकी देते हैं कि ईसाई धर्म मानते हो, गांव में शादी किए तो घर जला देंगे। दूल्हा बरात से गायब हो जाएगा। पीड़ित परिवार ने शादी रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। गौरतलब है कि धर्मांतरण के चलते लगातार उत्तर बस्तर कांकेर में तनाव के माहौल बनते रहते हैं। बहरहाल प्रशासन ने पीड़िता का आवेदन लेकर सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही है।

नगपुरा में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस संकाय के लिये नया कॉलेज

- **रसमड़ा में नया आई.टी.आई. शुरू किए जाने की मुख्यमंत्री ने की घोषणा**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेलअपने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान के तहत दुर्ग जिले के ग्राम पुरई पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पुरई में भेंट-मुलाकात के दौरान 78 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने हितग्राही मूलक योजना के तहत शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को सामग्री का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री ने शहीद श्री लोकेश साहू की मूर्ति स्थापना के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि शासकीय योजनाओं से सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को उनकी उपज को उचित कीमत में खरीदी के साथ बोनस दे रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर और राजगीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री को भेंट-मुलाकात के दौरान ग्राम रिसामा की श्रीमती उर्वशी चंद्राकार ने बताया कि उनके पास आधा एकड़ खेत है और उनका ऋण माफी योजना के तहत 20 हजार रुपए का कृषि ऋण माफ हुआ है। श्री रमेश कुमार गजपाल ने बताया कि उन्होंने अब तक सवा लाख रूपए का धान बेचा और इससे हार्वेस्टर खरीदा। किसान श्री तोषण कुमार साहू ने बताया कि उन्होंने 120 क्विंटल धान बेचा है और उनका

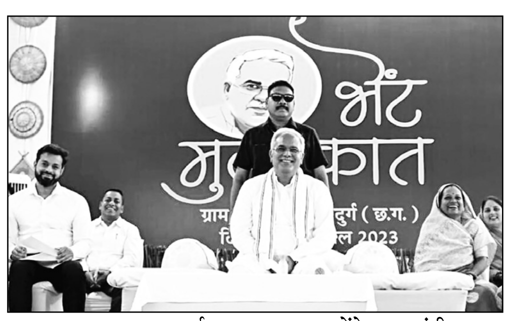

26 हजार रुपए का कर्ज माफ हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि अब प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान बेचने पर उन्हें 5 हजार रूपए का अतिरिक्त लाभ होगा। श्री थानेश्वर साहू ने मुख्यमंत्री को अपनी स्वरचित कविता सुनाई। शहीद श्री लोकेश साहू के नाम पर प्रतिमा लगाए जाने पर श्री थानेश्वर ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

ग्राम रसमड़ा के श्री देवेंद्र कुमार वैष्णव ने बताया कि रसमड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वहां कृषि भूमि नहीं है और औद्योगिक समूह उन्हें नौकरी नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारी से जानकारी ली। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि अब तक जिले में 1037 लोगों को रोजगार मिल चुका है। मुख्यमंत्री द्वारा भेंट-मुलाकात के दौरान राशन कार्ड के बारे में जानकारी लेने पर हितग्राही नॉमिन साहू ने बताया कि उनके घर मे 5 सदस्य हैं और उन्हें चावल, शक्कर, नमक सब राशन मिल रहा है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के कक्षा दसवीं के छात्र अद्वितीय निरंकारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि मुझे इस योजना से लाभ हुआ, महंगी स्कूल के फीस से राहत मिली, पहले स्कूल में 80 हजार रुपये फीस देना पड़ता था। अद्वितीय ने मुख्यमंत्री से सीबीएसई बोर्ड करने की मांग की। मुख्यमंत्री द्वारा हाटबाजार क्लिनिक योजना के बारे में जानकारी लेने पर ग्राम उतई की श्रीमती राशि बंजारे ने बताया कि मुझे इस योजना से स्वास्थ्य लाभ मिला है। मुझे इंस्पायर अवार्ड में जो राशि मिली, उससे मैंने अपने भाई के लिए मोबाइल खरीदा है। सुश्री शशि ने मुख्यमंत्री को बताया कि उसके भाई का नीट की परीक्षा से अम्बिकापुर में चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्हें भाई की पढ़ाई के लिए सहायता राशि की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने शशि की तारीफ करते हुए ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बेटी हंसिका को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के बारे में पूछे जाने पर श्रीमती सरस्वती ने बताया कि उनका बेटा लक्ष्य शारीरिक रूप से दिव्यांग था। सुपोषण योजना के तहत आंगनबाड़ी में नियमित रूप से गर्म दूध, केला और पोषक खाद्य सामग्री मिलने से अब जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

होम थियेटर बना बम, धमाके के बाद दूल्हे समेत रिश्तेदार की मौत

कवर्धा। शादी वाले घर में मातम पसरने की एक खौफनाक खबर जिले से आई है।जहां शादी के दो दिन बाद दूल्हे की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दूल्हे ने शादी में मिले गिफ्ट, होम थियेटर को चालू करने के लिए जैसे ही बिजली के बोर्ड से कनेक्शन किया।वैसे ही जोरदार धमाका हुआ।जिसमें दूल्हे की मौके पर मौत हो गई।वहीं हादसे में सात लोग जख्मी हुए हैं।धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घर की छत भी उड़ गई।

कवर्धा जिले के रेंगाखार थाना क्षेत्र के चमारी गांव में हेमेंद्र मेरावी की नई नई शादी हुई थी। उसे शादी में किसी ने होम थियेटर गिफ्ट में दिया था।दूल्हे ने पैकिंग खोली और होम थियेटर को कनेक्शन देने के लिए बिजली दौड़ाई।लेकिन जैसे ही पावर प्लग ऑन हुआ होम थियेटर में धमाका हो गया। धमाके में दूल्हा नहीं बचा। गांववालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद धमाके के शिकार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।चश्मदीदों की माने तो बाजू वाले कमरे से धमाके की आवाज आई थी।आकर देखने पर पता चला कि हादसा हुआ है। जिसमें कई लोग जख्मी थे। इस हादसे में अब तक कुल दो लोगों की मौत हुई है। जिले के एएसपी मनीषा ठाकुर रावटे ने बताया कि रेंगाखार थाना क्षेत्र के चमारी गांव में वैवाहिक घर के अंदर होम थियेटर में ब्लास्ट हुआ है। इस हादसे में युवक की मौत हो गई है। इसके अलावा एक और शख्स की मौत हो गई है। वहीं छह लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दुर्ग की जलपरी चंद्रकला पर देश की निगाहें, तैराकी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए हैं तैयार

दुर्ग। पुरई गांव के बच्चे विभिन्न खेलों में अपना परचम लहरा रहे हैं और गांव के ही तालाब में तैराकी की प्रैक्टिस कर बेहतर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस छोटे से गांव की ही, गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली चंद्रकला ओझा नया कीर्तिमान रचने के लिए इन दिनों कड़ी मेहनत कर रहीं हैं। 9 अप्रैल के दिन चंद्रकला सुबह पांच से दोपहर एक बजे तक यानी लगातार 8 घंटे तक तैरकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराएंगी। इससे पहले 6 घंटे तक तैरने का रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे तोड़ेने के लिए चंद्रकला रोजाना कोच ओम ओझा की निगरानी में सुबह, शाम 6 से 7 घंटे तैरने की प्रैक्टिस कर रहीं हैं।भाई बहन को देखकर स्विमर बनने का देखा सपना- चंद्रकला के बड़े परिवार में 20 से ज्यादा भाई बहन स्विमर हैं, जिन्हें देखकर ही उसने भी तैराकी को चुना। महज 6 साल की छोटी सी उम्र में पहली बार चंद्रकला तैराकी के लिए स्विमिंग पूल में उतरीं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में चंद्रकला की डाइट का खर्चा फ्लोटिंग विंग्स स्विमिंग एकेडमी उठा रही है।

छत्तीसगढ़ में पहली बार बना खेल प्राधिकरण, सभी खेलों को मिलेगा बढ़ावा- गुरुचरण सिंह होराचंद्रकला पर टिकी निगाहें- चंद्रकला ओझा फ्लोटिंग विंग्स स्विमिंग एकेडमी से जुड़कर अभ्यास कर रही हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में अपना नाम शामिल कराने के लिए इन दिनों कड़ी मेहनत कर रहीं हैं। 2019 में वह, गुजरात में ओलंपिक की तैयारी में लगी हुई थीं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से चन्द्रकला को वापस घर लौटना पड़ा था।

टेकारी में नहर नाली पुनरोद्धार के बाद सिंचाई समस्या

रायपुर। जल उपभोक्ता संस्था टेकारी के अंतर्गत आने वाले नहर नाली के पुनरोद्धार के बाद इसके शुरुआती ग्राम टेकारी को ही बीते 6 वर्षों से सिंचाई समस्या से जूझना पड़ रहा है । पूर्व में पदस्थ अधिकारियों द्वारा ध्यानाकर्षण के बाद भी इस समस्या से निजात दिलाने में कोताही बरतने से आक्रोशित ग्रामीणों ने सिंचाई पंचायत के अध्यक्ष रहे भूपेन्द्र शर्मा के माध्यम से बीते दिनों जल संसाधन मंत्री रवीन्द्र चौबे को? ज्ञापन सौंप इस समस्या की ओर ध्यानाकृष्ट कराया था जिसके बाद जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 के कार्यपालन अभियंता एम बोरकर ने अपने अधीनस्थों को आनन फानन में भेज इस नहर नाली में निस्तारी पानी दौड़ने के बीच निरीक्षण कराया । मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समस्या से रुबरु हो इससे निजात दिलाने का आश्वासन दिया ।

ज्ञातव्य हो कि महानदी जलाशय परियोजना के अधीनस्थ आने वाले जल प्रबंध संभाग एक के उपसंभाग 4 के अधीन आता है टेकारी जल उपभोक्ता संस्था । इस संस्था के अधीन आने वाले वितरक शाखा 24 से 6 ग्राम टेकारी , कुंडा , कठिया , सोनभट्ठा , अमेरी व सकरी के तकरीबन 3000 हजार एकड़ खेत को खरीफ सिंचाई हेतु पानी मिलता है । सिंचाई पानी पाने वाले इन ग्रामों में से टेकारी का

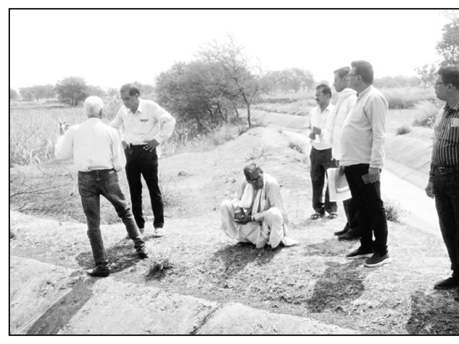

अधिकारियों ने किया निरीक्षण

रकबा शेष ग्रामों के रकबे के बराबर है । लगभग 7 साल पहले इस नहर नाली के रिमाडलिग व लाइनिंग का काम शासन द्वारा कराया गया था । टेकारी के अनुभवी ग्रामीणों ने निर्माण के दौरान ही टेकारी में सिंचाई पानी की दिक्कत आने की संभावना व्यक्त की थी जिसे तत्कालीन अधिकारियों ने अनदेखा कर निर्माण कार्य करा दिया था । निर्माण के बाद पहली सिंचाई पानी आते ही ग्रामीणों की आंशका सही साबित हुयी और तकनीकी कारणों से पर्याप्त सिंचाई पानी मिलने में दिक्कत शुरू हो चला । ध्यानाकर्षण पर मौजूदा अधिकारीगण स्थायी हल निकालने ?का आश्वासन दे खरीफ सिंचाई के लिये फौरी अस्थायी व्यवस्था कर पानी पहुंचाते रहे पर इस प्रयास में पूरे सिंचाई के दौरान टेकारी के किसानों को नहर नाली की सतत् चौकसी के साथ रतजगा करना पड़ता है ।श्री चौबे को प्रदत्त ज्ञापन में यह जानकारी देते हुये बतलाया गया है कि पूर्व में पदस्थ रहे एक अनुविभागीय अधिकारी श्री सारस्वत ने पूरे सिंचाई के दौरान लगातार निरीक्षण कर इस समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया था पर इसी बीच स्थानान्तरण हो जाने की वजह से समस्या यथावत रही । वर्तमान ई ई एम बोरकर का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने के साथ ही सिंचाई मंत्री श्री चौबे को ज्ञापन सौंप इस समस्या से स्थायी निजात दिलाने का आग्रह बीते 28 मार्च ?को ज्ञापन सौंप किया गया था । इसके तुरंत बाद नवरात्रि नवमी के दिन ही श्री बोरकर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी ए के पाटिल ए ई आर एल गौतम व आर के डेंगरे , अमीन चंद्रहास साहू , समयपाल रामेश्वर साहू के साथ समस्या स्थल पर सिंचाई पंचायत अध्यक्ष रहे भूपेन्द्र शर्मा , ग्रामीण सभा के अध्यक्ष रामानंद पटेल व पूर्व अध्यक्ष हुलास राम वर्मा , सरपंच नंद कुमार यादव के साथ निस्तारी पानी चलने के दौरान ही निरीक्षण किया व विभागीय अभिलेखों से रकबो का मिलान कर समस्या से स्थायी निजात दिलाने व्यवस्था का आश्वासन दिया ।

संपादक के पास 'सम्यक दृष्टि' होनी चाहिए- गिरीश पंकज

राकेश शर्मा को मिला 15वां पं. बृजलाल द्विवेदी साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान

इंदौर। देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका 'वीणा' (इंदौर) के संपादक राकेश शर्मा को मीडिया विमर्श परिवार द्वारा रविवार को इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित सम्मान समारोह में 15वें पं. बृजलाल द्विवेदी स्मृति अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि प्रख्यात साहित्यकार गिरीश पंकज ने कहा कि संपादक के पास 'सम्यक दृष्टि' होनी चाहिए, जो मोती चुने, लेकिन आज मोती चुनने वाले संपादक कम होते जा रहे हैं। 'वीणा' के संपादक राकेश शर्मा उसी 'हंस दृष्टि' के संपादक हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा ने की। आयोजन में प्रयागराज से प्रकाशित होने वाली प्रतिष्ठित पत्रिका 'सरस्वती' के संपादक रविनंदन सिंह, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. विकास दवे और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के पत्रकारिता विभाग की अध्यक्ष डॉ. सोनाली नरंगुदे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन एवं इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविन्द तिवारी भी मौजूद थे।

साहित्यिक पत्रकारिता के महत्व पर गिरीश पंकज ने कहा कि साहित्यिक पत्रकारिता न केवल हमें सूचित करती है, शिक्षित करती है, बल्कि हमें संस्कारित भी करती है। आज के साहित्यकारों को साहित्यिक पत्रकारिता की दिशा पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विचार, राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों एवं चिंताओं को लेकर 'वीणा' प्रकाशित हो रही है। इसीलिए 'वीणा' को साहित्यिक पत्रकारिता का 'सुंदर कांड' कहा जा सकता है।

सभ्य समाज में होता है साहित्यकारों का सम्मान-मेहरा

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा ने कहा कि वह समाज सभ्य समाज है, जो साहित्यकारों का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि साहित्य यशस्वी होगा, तो हमारा राष्ट्र यशस्वी होगा। उन्होंने बाबा भारती की कहानी का जिक्र करते हुए कहा कि भरोसे को पैदा करना साहित्य का काम है और उसका संरक्षण करना पत्रकारिता की जिम्मेदारी है।

इसके अलावा अब तक यह सम्मान 'दस्तावेज' (गोरखपुर) के संपादक डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, 'कथादेश' (दिल्ली) के संपादक हरिनारायण, 'अक्सर' (जयपुर) के संपादक डॉ. हेतु भारद्वाज, 'सद्भावना दर्पण' (रायपुर) के संपादक गिरीश पंकज, 'व्यंग्य यात्रा' (दिल्ली) के संपादक डॉ. प्रेम जनमेजय, 'कला समय' (भोपाल) के संपादक विनय उपाध्याय, 'संवेद' (दिल्ली) के संपादक किशन कालजयी, 'अक्षरा' (भोपाल) के संपादक कैलाशचंद्र पंत, 'अलाव' (दिल्ली) के संपादक रामकुमार कृषक, 'प्रेरणा' (भोपाल) के संपादक अरुण तिवारी, 'युगतेवर' (सुल्तानपुर) के संपादक कमल नयन पाण्डेय, 'अभिनव इमरोज़' (दिल्ली) के संपादक देवेन्द्र कुमार बहल एवं 'साहित्य परिक्रमा' (राजस्थान) के संपादक डॉ. इंदुशेखर तत्पुरुष को दिया जा चुका है।

इस अवसर पर प्रख्यात साहित्यकार कृष्णबिहारी मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार डॉ. वेदप्रताप वैदिक एवं अभय छजलानी तथा मीडिया शिक्षक पुष्पेंद्र पाल सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। कार्यक्रम का संचालन अंकुर विजयवर्गीय ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन मुकेश तिवारी ने दिया।

तेंदूपत्ता तोड़ाई का पिछले साल का भुगतान नहीं, पूर्व वनमंत्री ने डीएफओ पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

भाजपा ने किया डीएफओ कार्यालय का घेराव

बीजापुर। तेन्दुपत्ता हितग्राहीयों के भुगतान को लेकर भाजपा ने दुसरी बार मोर्चा खोला और भाजपा कार्यालय में सभा के बाद डीएफओ कार्यालय घेरने पहुचें जहां अधिकारी और नेताओं और हितग्राहियों के बीच काफी तनातनी हुई डीएफओ के जवाब से असन्तुष्ट होकर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा कार्यकर्ताओं के साथ नेशनल हाईवे जाम कर उग्र प्रदर्शन किया प्रशासन की मोहलत के बाद नेताओं ने हाईवे छोड़ा।

विदित हो कि भैरमगढ़ ब्लाक के इन्द्रावती नदी के तट पर बसे आदिवासी ग्रामीणों का तेन्दुपत्ता तोड़ाई एवं वाहन ढुलाई समेत करोड़ों रूपये का भुगतान बीते एक वर्ष से नहीं हुआ है। जिसे लेकर भाजपा नेता महेश गागड़ा लगातार भुगतान की मांग कर रहे है। इसी तारतम्य में दस दिन पूर्व नेलसनार में भाजपाईयों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर विरोध प्रदर्शन करते हुये भुगतान की मांग की थी, इस दौरान डीएफओ अशोक पटेल ने दस दिवस का भुगतान संबंधी आश्वाशन दिया था।

दिये गये समय अनुसार भुगतान नहीं होने को लेकर पूर्व वनमंत्री

गागड़ा ने हितग्राही एवं कार्यकर्ताओं के साथ सभा के बाद डीएफओ कार्यालय घेरने पहुचें , जहां अधिकारी की गोलमोल जवाब को लेकर तनातनी का माहौल निंमित हुई जिसके बाद डीएफओ के जवाब से अतुंष्ट भाजपाई उग्र हुए और नगर के बीचो-बीच नेशनल हाईवे जाम कर धरने पर बैठ नारे बाजी करने लगे।

पुलिस के द्वारा समझाइश के बाद भी नेता नहीं उठे , वहीं कार्यकर्ताओं को उग्र होता देख एसडीएम और तहसीलदार पहुचें, और नेताओं की बात सुनी व भुगतान करने हेतु बीस दिनों का समय मांगा है। इसके बाद धरना दे रहे भाजपाई धरने से उठ गए। इस दौरान जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार, सतेन्द्र ठाकुर, गोपाल सिंह पवार, लवकुमार रायडू, उर्मिला तोकल, नदकिषोर राणा, फुलचन्द गागड़ा, घासीराम नाग, बलदेव उरसा, चमन ठाकुर, चिन्नाराम तेलम , संदीप तेलम , सुनील तेलम, नीता शाह, रंजना, माया झाडी, पूजा पोदी, पुष्पा सिन्हा आदि मौजूद थे।

अप्रैल के तीसरे सप्ताह से तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य होगा शुरू

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 के दौरान तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य चालू माह अप्रैल के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगा। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज पिंगुआ तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री संजय शुक्ला के मार्गदर्शन में वर्ष 2023 में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य के सुचारू संचालन के लिए विभाग द्वारा तैयारियां जोरों पर है। इसके तहत समस्त जिला यूनियनों द्वारा फड़ मुशियों की नियुक्ति तथा अग्नि सुरक्षा और तेंदूपत्ता शाखकर्तन के संबंध में कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण आदि की कार्यवाही तेजी से जारी है। राज्य लघु वनोपज संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष तेन्दूपत्ता विक्रय उपरांत आगे की कार्यवाही ऑनलाइन करने के लिए पोस्ट बिड सेल मैनेजमेंट साफ्टवेयर तैयार कराया गया है। जिससे क्रेता नियुक्ति आदेश, क्रेताओं द्वारा क्रेता करारनामा तथा अन्य कार्य को ऑनलाइन सम्पादन किया जायेगा। जिससे दूर-दराज के क्रेताओं को अपने स्थान से ही समस्त कार्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा सकेगा। लघु वनोपज संघ द्वारा तेंदूपत्ते का संग्रहण से पूर्व उसके गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि संग्राहक उच्च गुणवत्ता का तेन्दूपत्ता का संग्रहण करें, जिससे उन्हें संग्रहण पारिश्रमिक अधिक से अधिक प्राप्त हो सकें। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 से तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 2500 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रूपए प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है।

मेरी बात — ✍ गिरीश पंकज

साहित्यिक पत्रकारिता के निहितार्थ

पिछले दिनों में इंदौर में था। पंडित बृजलाल द्विवेदी स्मृति साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान के आयोजन में । 96 साल से निकल रही साहित्यिक पत्रिका %वीणा% के संपादक राकेश शर्मा को सम्मानित करना था। पिछले 15 वर्षों से %मीडिया विमर्श% के सलाहकार संपादक और इस समय भारतीय जनसंचार माध्यम के महानिदेशक डॉ संजय द्विवेदी अपने दादा के की स्मृति में हर साल एक श्रेष्ठ पत्रिका को सम्मानित करते हैं। वीणा का सम्मान श्रेष्ठ साहित्य पत्रकारिता का सम्मान है ।साहित्य निरंतर बेहतर के लिए प्रेरित करने वाली प्रविधि है । और इस कार्य को गति देने का काम साहित्यिक पत्रिकाएं करती हैं, श्रेष्ठ कृतियों का प्रकाशन करके। ऐसा होता रहा है। पत्रिका को कायदे से हंस की तरह मोती चुनने चाहिए, लेकिन जब संपादक ही कौवा बन जाए तो वह मोती नहीं, कुछ और चुगता है। आज अगर साहित्य की पत्रकारिता अलोकप्रिय हो रही है, संक्रमण से जूझ रही है,तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि अब वैसे महाप्राण संपादक नहीं रहे, जैसे दशकों पहले हुआ करते थे। जिसके बारे में कभी बाबूराव विष्णु पराड़कर ने कहा था कि भविष्य में अखबार तो बेशक चमकदार होंगे, लेकिन वहां महाप्राण संपादक नहीं रहेंगे। अब ऐसे साहित्यिक सम्पादक दुर्लभ हैं, जिन्होंने कभी साहित्यिक पत्रकारिता को जागरण का मंच बनाया था। आज मैं जब कुछ पत्रिकाओं को देखता हूँ, तो हैरत होती है । उसकी प्रकाशित सामग्री वितृष्णा पैदा करती है। ज्यादातर कविताएं अबूझ पहेली की तरह लगती हैं। कहानियों में कहानीपन गायब है। एक वरिष्ठ आलोचक ने कभी कहा था कि आज की कहानियों को देखकर नाक बंद करने की इच्छा होती है। लेखों में प्रगतिशीलता के नाम पर अराजकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा, लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिकता का गुणगान करना फैशन हो गया है। भारतीयता का, राष्ट्रीयता का बोध सिरे से गायब है। भारतीयता या राष्ट्र की बात करते ही कुछ लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। तब मुझे गयाप्रसाद शुक्ल सनेही की कविता याद आती है, जो कहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से/ जिसमें बहती रसधार नहीं /वह हृदय नहीं है पत्थर है/ जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं । आजादी के संघर्ष के दौरान लिखी गई ये पंक्तियां आज भी हमें याद रखनी चाहिए क्योंकि मैंने महसूस किया है कि धीरे-धीरे नई पीढ़ी देश के प्रति प्रेम कम हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, तो इस देश में भारत तेरे टुकडे होंगे और सिर तन से जुदाजैसे निकृष्ट नारे क्यों लगते? इसीलिए आज राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की पंक्तियों को भी याद करने की ज़रूरत है, हम कौन थे और क्या हो गए, और क्या होंगे अभी। इस दिशा में आत्म-मंथन करना होगा। सोचें कि हम अभी और कितने पतित होंगे। जब समाज का एक बड़ा वर्ग फटी हुई जींस पहन कर आधुनिकता की नई परिभाषा गढ़ रहा हो, तो समझना चाहिए कि हमारी दृष्टि कितनी भोथरी हो गई है । यही हाल साहित्यिक पत्रिकाओं का भी है, जहां विचारों की जींस फटती चली जा रही है । विचार नग्न होकर खड़े होने की तैयारी में है। तब यह जरूरी है कि कुछ मूल्य तो बचें। यह काम केवल मानवीय और भारतीय मूल्यों से अनुप्राणित साहित्यिक पत्रिकाएं ही कर सकती हैं। जो साहित्य का अर्थ सत्यम, शिवम, सुंदरम से लगाती हैं। जिनके लिए कला केवल कला नहीं, जीवन का एक उपक्रम है। लेकिन कई बार हम लाचार हो जाते हैं, क्योंकि यस्य नास्ति स्वयंप्रज्ञा शास्त्रम कस्य करोति किम? जिसने अपनी बुद्धि खुद नष्ट कर ली हो, उस बेचारे के लिए शास्त्र क्या कर सकता है ? अब समय आ गया है कि विद्रूपता और स्मृति-भंग के शिकार समाज को फिर उसके गौरवशाली अतीत के बारे में बताया जाए। हमें आगे बढ़ना है। मगर पीछे देखते हुए भी चलना है। सिर्फ आगे ही आगे देखना ठीक नही। जब हम पीछे देखेंगे तो हमें वहां सरस्वती दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ मित्र दिखेगा। चांद दिखेगा। प्रताप दिखेगा। हरिश्चंद्र चन्द्रिका, बालाबोधिनी ,कवि वचन-सुधा, हिंदी प्रदीप, सुदर्शन, इंदु, प्रभा, माधुरी कल्पना, लहर, ज्ञानोदय, नया खून, साहित्य संदेश आदि महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाएं दिखाई देंगी। उन्हें हम अपना आदर्श मानकर चलें, तो आज भी साहित्यिक पत्रकारिता मूल्यवान हो सकती है। धर्मयुग, दिनमान,सारिका और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाओं को भी हम याद कर सकते हैं। भले ही ये बड़े घरानों की पत्रिकाएं थीं, लेकिन इनको कुछ सुयोग्य साहित्यिक संपादक मिले, जिनके कारण इनमें कुछ हद तक साहित्यिकता भी नज़र आती थी। इसलिए हमें पलट कर देखना होगा। कभी हम भोपाल जाएं, तो पंडित माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय जाकर वहां रखी हुई पुरानी दुर्लभ पत्रिकाओं का अवलोकन करें, तो हमें अपने समृद्ध अतीत के बारे में पता चलेगा। आज साहित्यिक पत्रकारिता को उस परंपरा का अनुगमन करते हुए ही आगे बढ़ना है। हमारा प्राचीन चिंतन कहने को प्राचीन है, लेकिन उसकी दृष्टि आज भी अर्वाचीन है, प्रगतिशीलता और आधुनिकता से लबरेज है। चाहे केरल के नारायण गुरु हों, या उत्तर के कबीर-तुलसी, या महाराष्ट्र के नामदेव,संत ज्ञानेश्वर, समर्थ रामदास आदि ; इन सब का चिंतन मानवता का संदेश देने वाला है। इन सब का पुनरपाठ साहित्यिक पत्रिकाओं में निरंतर होना चाहिए । और अंत में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि साहित्यिक पत्रिकाएं केवल लेखक की पत्रिका बन कर रह जाएं, वरन समूचे परिवार की पत्रिका बनें। अपने दौर में सरस्वती जैसी पत्रिका में केवल कविता, कहानी भर नहीं छपा करती थी, दूसरे सामाजिक मुद्दे पर छपा करते थे । महिलाओं और बच्चों के लिए भी उसमें रचनाएं प्रकाशित होती थी। अगर साहित्यिक पत्रकारिता में बाल साहित्य और स्त्रियोचित बातों को भी स्पेस मिलने लगे, तो धीरे-धीरे पूरे परिवार की रुचि साहित्यिक पत्रिका को पढ़ने में विकसित होगी। अगर इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है, साहित्यिक पत्रकारिता के साथ समग्रता में न्याय कर सकेंगे। साहित्यिक पत्रकारिता का निहितार्थ ही यही है कि समाज का मानसिक उन्नयन हो, उसे कुछ बौद्धिक खुराक मिले।

संक्षिप्त खबरें

मोदी से कल मिलेंगे भाजपा विधायक

पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली जाकर सूबे के भाजपा विधायक प्रधानमंत्री मोदी से सामूहिक मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि पार्टी इसे शिष्टाचार भेंट बता रही है लेकिन चुनावी मोड में जब सियासी हलचल शुरू हो चुकी है मुलाकात के मायने तो समझ आ रहा है। उनकी साझा बैठक 5 अप्रैल को है,कुछ रवाना हो गए हैं तो कुछ कल जा रहे हैं। माना जा रहा है कि केन्द्र की योजनाओं का क्रियान्वयन को लेकर वे पीएम से चर्चा कर सकते हैं। बस्तर या सरगुजा या फिर रायपुर में कोई कार्यक्रम में शामिल होने वे मोदी को आमंत्रित भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के भाजपा सांसद दिल्ली रवाना हो चुके हैं। सोमवार को इनकी मुलाकात देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हो रही है। राष्ट्रपति बनने के बाद से स्थानीय सांसदों से पहली बार द्रोपदी मुर्मू मुलाकात कर रही हैं। यह औपचारिक मुलाकात होगी।

ईडी प्रदेश में ऑपरेशन कमल में लगी है, कांग्रेस नेताओं ने कहा

रायपुर। पिछले दिनों जिन कांग्रेस नेताओं के घर ईडी ने छापेमारी की थी उन्होने सामूहिक पीसी लेकर कहा कि ईडी प्रदेश में ऑपरेशन कमल में लगी है,उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी प्रदेश में ऑपरेशन कमल में लगी है। दोनों नेताओं ने कहा कि ईडी को खुलासा करना चाहिए, कि किस प्रकरण की जांच कर रही है, और जिन लोगों के यहां छापेमारी की गई है। उनके यहां अब तक क्या बरामदगी हुई है? ईडी ने खनिज निगम के अध्यक्ष देवांगन, महापौर एजाज ढेबर, सन्नी अग्रवाल, और अचल भाटिया सहित कई अन्य लोगों के यहां छापेमारी की थी। ये सभी सोमवार को राजीव भवन में मीडिया से रूबरू हुए। खनिज निगम के चेयरमैन देवांगन ने कहा कि ये जानकारी आई है

कि छापे की शुरूआत किसी कोयले प्रकरण की वजह से हो रही है। मगर वो न तो कोयले के व्यापार से जुड़े हैं, और न ही उनका परिवार कोयले के कारोबार में है। खनिज निगम के चेयरमैन जरूर हैं, लेकिन वहां भी कोयले का कारोबार नहीं है।देवांगन ने आगे कहा कि ऐसे में उनके यहां किस उद्देश्य से छापेमारी की गई है। यह अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए भूपेश बघेल के साथ काम करते रहे हैं। उन्हें महाधिवेशन में अहम जिम्मेदारी दी गई। छापेमारी महाधिवेशन को प्रभावित करने की कोशिश थी। उन्होंने कहा कि लगातार छापेमारी हो रही है। उन्होंने कहा कि छापों का डर नहीं है, लेकिन किसके यहां कितनी संपत्ति मिली है। क्या बरामद हुआ है, यह बताना चाहिए? महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि उनके यहां छापे डाले गए, लेकिन किस वजह से छापेमारी की गई। यह ईडी के अफसर नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि ईडी की टीम उनके यहां सर्च वारंट लेकर आई थी, लेकिन उनके भाई के यहां भी जाकर सारे समान को उलट-पुलट कर दिया। यह सब किसके इशारे पर हो रहा है।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

युवा कांग्रेस पीएम से मांगेगे अडानी से जुड़े तीन सवालों का जवाब

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा आज रायपुर के राजीव भवन में पोस्टकार्ड अभियान को लेकर प्रेस वार्ता की गई इस अभियान में प्रदेश के 90 विधानसभाओं में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पोस्टकार्ड

अभियान चलाया जाएगा। इस पोस्टकार्ड अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तीन महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे और युवा कांग्रेस द्वारा 90 विधानसभाओं में एक लाख से अधिक पोस्टकार्ड युवाओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष आकाश आकाश शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार देश में आज लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है इसका एक उदाहरण हमारे नेता राहुल गांधी जब भी संसद में अडानी को लेकर सवाल पूछते थे तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता था और उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था अब एक झूठे मामले में फंसा कर राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द कर दी गई इस अभियान के तहत 90 विधानसभाओं में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी युवाओं के पास जाकर उनके नाम नंबर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तीन सवाल पूछेंगे और 90 विधानसभाओं में एक लाख से अधिक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे जाएंगे यह अभियान 25 दिनों तक पूरे प्रदेश में चलेगा।

भाजपा नेता की हत्या मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी से लगे तिल्दा इलाके में शुक्रवार को हुई भाजपा नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है वहीं फरार अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। जहां 31 मार्च को भाजपा नेता जितेंद्र पाल एवं उसके पुत्र आयुस पाल पर जलसो गांव के आशु, ईशु ,फेन्टा, रवि एवं उसके अन्य साथियों ने घर में जबरन घुसकर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का और चाकू, पत्थर, लाठी, डंडा वगैरह से मारपीट की। इस घटना में गंभीर रूप से घायल जितेन्द्र पाल की मौत हो गई थी वहीं पुद्ध आयुष गंभी रूप से घायल हुआ था। वहीं आरोपी फरार हो गये थे। जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने लगातार रेड कार्रवाई कर वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है था उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 कार और एक बाइक जब्त किया है। मामले में पुलिस ने आशु उईके पिता मुन्ना उईके उम्र 26 साल निवासी ग्राम जलसो थाना तिल्दा नेवरा , शुभम घोष उर्फ राजा पिता सुप्रिया घोष उम्र 26 साल निवासी हिमालयन हाईट्स थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर,विकास घोष उर्फ सुभाष घोष पिता सुप्रिया घोष उम्र 24 साल निवासी हिमालयन हाईट्स थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर,बलराम यादव उर्फ राजा पिता इन्दरभान यादव उम्र 29 साल निवासी ग्राम कुंदरू थाना तिल्दा नेवरा रायपुर तथा शिव कुमार उईके पिता कोदू उईके उम्र 26 साल निवासी ग्राज जलसो थाना तिल्दा नेवरा रायपुर को गिरफ्तार किया है।

भीड़ के दम न्यायालय पर दबाव डालने में राहुल के साथ भूपेश भी जिम्मेदार-भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी शैलजा आदि का गुजरात दौरा व्यक्तिगत पूजा और चाटुकारिता की

हद है। श्री मूणत ने कहा कि दोष सिद्धि के बाद राहुल गांधी को यदि सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करनी ही थी तो वे तुरंत कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं करके उन्होंने न्यायपालिका और संवैधानिक प्रक्रिया के अपमान की पराकाष्ठा की और बघेल, गहलोत व शैलजा आदि कांग्रेस के नेताओ ने भीड़ के दम पर न्यायलय पर दबाव डालने का प्रयास किया है जो निदनीय है श्री मूणत ने कहा कि सत्याग्रह, मशाल रैली जैसी राजनीतिक नौटंकियां करके देश व प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने राजनीतिक सद्भाव को तो खत्म किया ही, राहुल गांधी की सजा और सदस्यता समाप्ति के तथ्यों को छिपाकर देश को गुमराह करने का कृत्य भी किया है। श्री मूणत ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को इस मुद्दे पर झूठ फैलाकर देश के संसाधनों व समय को अनावश्यक रूप से खर्च करने के लिए देश व प्रदेश से नि:शर्त माफी मांगनी चाहिए।

कांग्रेस नेताओं का चेहरा कोयले की कालिख से पुता हुआ है- बृजमोहन

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने ईडी के छापों को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार पत्रकार वार्ता लेकर सत्ताधारी कांग्रेस नेताओं

द्वारा ईडी की कार्रवाई को पूर्वाग्रह और खुद को निर्दोष बताना उनकी बेचैनी प्रदर्शित कर रहा है। इस दौरान उनकी भाव भंगिमा और माथे की शिकन बता रही है कि दाल में जरूर कुछ काला है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले से ही कह दिया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। यही वजह है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां पूरी निष्पक्षता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी लोगों के घर में ईडी की कार्रवाई, ईडी के छापे उनकी इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस सत्ता में आई हैं उसके द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार खुली आंखों से हर कोई देख रहा है। विकास का नामोनिशान नहीं है परंतु उस विकास के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए डकारे जा चुके हैं।

श्रमिकों की शिकायतों पर सीएससी सेंटर्स पर कार्यवाही

रायपुर। श्रम विभाग छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन और अन्य श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के आवेदन प्रक्रिया सीएससी (लोक सेवा केन्द्र) के माध्यम से प्रावधानित किया गया है। सचिव छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने बताया है कि श्रमिकों द्वारा यह शिकायत की जा रही थी कि कुछ सीएससी सेंटर्स द्वारा श्रमिकों के पंजीयन एवं श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं के आवेदन के संबंध में श्रमिकों को परेशान किया जा रहा है तथा योजनाओं का फायदा श्रमिकों को नहीं मिल पाता है। श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित ऐसे सी.एस.सी सेंटर जो श्रमिकों के पंजीयन एवं श्रम विभाग की योजनाओं के आवेदन लेने में लापरवाही कर रहे है, ऐसे सेंटर्स को श्रम विभाग के कार्य किए जाने हेतु प्रतिबंधित किया गया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की सचिव ने जानकारी दी है कि रायपुर जिले के 15, बलौदाबाजार के 12, गरियाबंद के 9, धमतरी के 1, महासमुंद के 1, बिलासपुर के 5, कोरबा के 3, जांजगीर-चांपा 12, रायगढ़ 9, बस्तर 2, कोण्डागांव 3 सुकमा 1, नारायणपुर 1, सरगुजा 6, सूरजपुर 10, बलरामपुर 4, कोरिया 6, जशपुर 1, दुर्ग 11, राजनांदगांव 32, बालोद 12, बेमेतरा 19 और कवर्धा के 5 सीएससी सेंटर्स को श्रम विभाग के कार्य किए जाने हेतु प्रतिबंधित किया गया है।

सुपोषित छत्तीसगढ़ बनाने गांव-गांव हुआ पोषण पखवाड़े का आयोजन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में सुपोषित छत्तीसगढ़ के ध्येय से पोषण जागरूकता पखवाड़े का आयोजन किया गया। 20 मार्च से 03 अप्रैल तक चले इस पखवाड़े में बच्चों तथा महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जागरूकता और आदतों में सुधार लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पखवाड़े में सुपोषण रथ, पोषण साइकल/बाइक रैली, मैराथन, मिलेट्स जागरूकता कैम्प, सुपोषण चौपाल, अम्मा की रसोई का भी आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में महिलाओं और बच्चों के साथ ही पंचायत प्रतिनिधि, गांव के युवा, विभिन्न विभागों के अधिकारी और यूनिसेफ के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। महिला एवं बाल विकास विभाग संचालक श्रीमती दिव्या मिश्रा ने बताया कि पोषण पखवाड़े के दौरान प्रत्येक दिन के लिए कलेण्डर अनुसार गतिविधियां आयोजित की गई। इन गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर पोषण सम्बन्धित व्यवहार परिवर्तन का प्रयास किया गया। पोषण पखवाड़े के दौरान आयुष, पंचायत, कृषि सहित अन्य विभागों, जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग मिला।

धर्म बदलने पर जनजाति को आरक्षण का लाभ ना मिले-भगत

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा डीलिस्टिंग की मांग को लेकर आगामी 16 अप्रैल को एक बड़े आंदोलन एवं महारैली का आह्वान किया गया है। इस महारैली में हजारों की संख्या में जनजाति नागरिक शामिल होंगे, जिनकी एक ही मांग होगी डीलिस्टिंग। रायपुर स्थित स्वदेशी भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत, भोजराज नाग, रोशन प्रताप सिंह और श्रीमती संगीता पोयाम (सह-संयोजिका, जनजाति सुरक्षा मंच छत्तीसगढ़) ने बताया कि रविवार 16 अप्रैल को राजधानी के वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर के सामने इस भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली के माध्यम से जनजाति समाज की यह मांग है कि जिन नागरिकों ने अपनी मूल संस्कृति और अपने मूल धर्म को छोड़कर विदेशी धर्म (जैसे ईसाई या इस्लाम) अपनाया उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से

तत्काल बाहर किया जाए और इसके लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन किए जाए। चूंकि छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के द्वारा मूल जनजातियों के हिस्से की सुविधाओं को अवैध रूप से छीना जा रहा है, जिसमें आरक्षण भी एक प्रमुख तत्व है, इसलिए हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के जनजातियों के साथ-साथ देश के करोड़ों जनजातियों के साथ हो रहे अन्याय को रोका जाए और धर्मान्तरितों को डी-लिस्ट किया जाए।

छत्तीसगढ़ सहित भारत में धर्मांतरण स्वतंत्रता के पूर्व से ही भारत के अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। विदेशी धर्म के द्वारा छत्तीसगढ़ के लोगों का धर्म परिवर्तन कराना कोई नई घटना नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से इसमें भारी वृद्धि देखी गई है। इस तरह के धर्मांतरण जनजाति समुदाय को एक धीमे जहर की तरह प्रभावित कर रहे हैं और यह उनके मूल विश्वास, संस्कृति, रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों को समाप्त कर रहे हैं।

दरअसल जनजाति समाज को आरक्षण इसीलिए दिया गया है ताकि उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थितियों को ऊपर उठाया जा सके। लेकिन जनजाति आरक्षण का मूल उद्देश्य तब अर्थहीन हो जाता है, जब जनजाति अपने मूल विश्वास और संस्कृति एवं रीति-रिवाजों को अस्वीकार कर दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब कोई व्यक्ति अपने समुदाय की ही पहचान खो देता है तो वह अपनी मूल पहचान की रक्षा और उसे बनाए रखने के लिए दिए गए लाभों को उठाने का पात्र कैसे हो सकता है ?

इसीलिए अपनी मूल संस्कृति, रीति-रिवाजों, भाषाओं, परंपराओं एवं पुरखों की विरासत को बचाने के लिए जनजाति सुरक्षा मंच ने 16 अप्रैल को विशाल महारैली का आयोजन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से हजारों की संख्या में जनजाति समाज के लोग शामिल होंगे। हम सभी से इस बात का अनुरोध करते हैं कि विदेशी धर्मों से गरीब अनुसूचित जनजातियों को बचाने में और उनसे संघर्ष करने में हमारी सहायता करें, अन्यथा जनजाति समुदाय की बहुत सी पहचान और लक्षण कुछ ही समय में विलुप्त हो जाएगी।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.